RNI No. : TNHIN/2013/52520 ■ वर्ष - 13 ■ अंक - 280 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » शनिवार » 09-05-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 बिहार में जातिवाद और वंशवाद की राजनीति कर रहा राजग : तेजस्वी यादव

6 मणिपुर हिंसा : आक्रोश में अवसर तलाशता विपक्ष

7 बाहर से इमेज बनाना आसान है, असली खेल तो साफ दिल का है : नोरा फतेही

क्या विजय आज पहन पाएंगे 'ताज'?

टीवीके अध्यक्ष विजय ने सरकार बनाने के न्योते के लिए राज्यपाल से मुलाकात की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके के अध्यक्ष चंद्रशेखर जोसफ विजय ने वामपंथी दलों से समर्थन मिलने के बाद शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से लोक भवन में मुलाकात की ताकि उनसे सरकार बनाने का निमंत्रण प्राप्त किया जा सके। सूत्रों के अनुसार विजय पहले ही सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं लेकिन संख्याबल को लेकर राज्यपाल संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने बताया कि विजय की राज्यपाल से मुलाकात संक्षिप्त रही। वामपंथी दलों द्वारा बिना शर्त समर्थन देने का वादा करने के कुछ घंटों बाद, विजय गुइंडी में राज्यपाल के कार्यालय पहुंचे। टीवीके समर्थकों को उम्मीद है कि अर्लेकर उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) को 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीट मिली है जो बहुमत के लिए जरूरी 118 सदस्यों की संख्या से कम है। नतीजे आने के कुछ घंटों के बाद ही द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। पार्टी के सदन में पांच सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

विजय ने सरकार बनाने की कोशिशों के तहत द्रमुक की सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और विदुथालाई चिरुथैगल कच्ची (वीसीके) से संपर्क किया था। तीनों दलों के सदन में दो-दो विधायक हैं। भाकपा और माकपा ने विजय को समर्थन देने की घोषणा कर दी है जबकि वीसीके ने कहा कि वह शनिवार को फैसला लेगी।

पुडुचेरी: रंगासामी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया

पुडुचेरी/भाषा। ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस (एआईएनआरसी) प्रमुख एन रंगासामी ने शुक्रवार को उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन से मुलाकात कर पुडुचेरी में सरकार बनाने का दावा पेश किया। रंगासामी के साथ गठबंधन दलों के नवनिर्वाचित विधायक भी मौजूद थे। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि रंगासामी द्वारा प्रस्तुत पत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, रंगासामी 13 मई को पांचवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

शुभेंदु अधिकारी ने पेश किया बंगाल में सरकार बनाने का दावा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार शाम राज्यपाल आर एन रवि से मुलाकात की और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार बनाने का दावा पेश किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के दो घंटे बाद अधिकारी लोकभवन पहुंचे।

इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई शीर्ष नेता भी मौजूद थे, जिनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सुकांत मजूमदार और शांतनु ठाकुर, ओडिशा के मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल की बैठक के सह-पर्यवेक्षक मोहन चरण माझी, भाजपा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, और पार्टी की प्रदेश इकाई के अन्य वरिष्ठ नेता जैसे दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी और तापस रॉय शामिल थे।

प्रधानमंत्री और भाजपा के जाने का 'टाइम' आने वाला है : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुरुग्राम/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भले ही सोच रहे हैं कि इनका राज बना रहेगा, लेकिन इनका जाने का 'टाइम' आने वाला है तथा उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितना 'वोट चोरी' कर लें, लेकिन कांग्रेस उन्हें पराजित करेगी। राहुल गांधी शुक्रवार शाम यहां हरियाणा कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह की 'सद्भाव यात्रा' में शामिल हुए। सिंह पिछले कुछ महीने से हरियाणा में पदयात्रा निकाल रहे हैं।

'भारत जोड़ो यात्रा' में करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले राहुल गांधी पहली बार बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल हुए।

इस मौके पर बृजेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद व अन्य नेता भी थे।

राहुल गांधी ने यात्रा के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, '' हरियाणा का चुनाव भाजपा ने चोरी किया...अब पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव चोरी किया है। इन्होंने चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना दिया है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्वाचन आयोग, नौकरशाही को नियंत्रित कर रखा है।

चीन ने पिछले साल हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को मदद पहुंचाने की पुष्टि की

बीजिंग/भाषा। चीन ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि उसने पिछले साल भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को रण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की थी। चीन की आधिकारिक मीडिया ने यह जानकारी दी। चीन के सरकारी प्रसारणकर्ता 'सीसीटीवी' ने बृहस्पतिवार को देश के विमानन उद्योग निगम (एवीआईसी) के चेंगदू वायुयान डिजाइन एवं अनुसंधान संस्थान के इंजीनियर झांग हेंग का साक्षात्कार प्रसारित किया। एवीआईसी चीन के उन्नत लड़ाकू विमानों और मानवरहित वायुयान (यूएवी) का एक प्रमुख विकासकर्ता है।

09-05-2026 सूर्यास्त 6:25 बजे | 10-05-2026 सूर्योदय 5:44 बजे

BSE	NSE
77,328.19	24,176.15
(-516.34)	(-150.50)

सोना	चांदी
15,720 रु.	265,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

थूक फजीती

दल बाँट रहे महापुरुषों को,
अपनी खिसियाहट के कारण।
मृतकों को अपमानित करके,
लड़ रहे सियासत का वे रण।
कुछ शर्म करो दल धृतराष्ट्रों,
तक रहा वक्त तुमको प्रति क्षण।
इस थूक-फजीती को लख-सुन,
आक्रोशित है अब जन मन गण।।

अमेरिकी रक्षा विभाग जारी कर रहा उड़न तश्तरी से जुड़ी नई फाइल

वाशिंगटन/एपी। अमेरिकी रक्षा विभाग 'पेंटागन' ने उड़न तश्तरी (यूएफओ) से संबंधित नई फाइल जारी करते हुए कहा है कि आम लोग ''अज्ञात असामान्य घटनाओं'' पर अपने निष्कर्ष खुद निकाल सकते है। पेंटागन के अलावा, इस कवायद का नेतृत्व व्हाइट हाउस, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक, ऊर्जा विभाग, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एफबीआई (संघीय जांच ब्यूरो) आदि कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि एक ओर जहां पूर्ववर्ती सरकारों ने अमेरिकी नागरिकों को बदनाम करने या हतोत्साहित करने की कोशिश की।

सत्यमेव जयते
Government of India

सुनिश्चित सुरक्षा, संरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करने के 11 वर्ष का जश्न

अब तक लगभग 95 करोड़ संयुक्त नामांकन के साथ असुरक्षितों को सुरक्षा कवच

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज
2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64% हुआ – 45% की वृद्धि
- आईएलओ

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
किफायती जीवन बीमा कवर
₹436 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर
27+ करोड़ से अधिक नामांकन
व्यापक पात्रता
18-50 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जिनका बैंक या डाकघर में खाता है
आसान नामांकन एवं नवीनीकरण
बैंक/डाकघरों के माध्यम से सरल पंजीकरण तथा वार्षिक ऑटो-डेबिट सुविधा

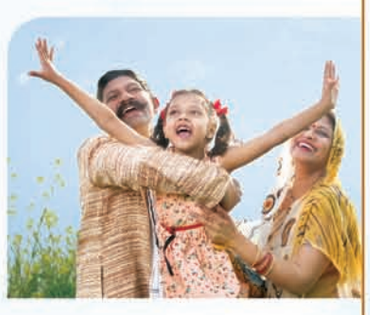

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
दुर्घटना बीमा कवर
₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख का आकस्मिक मृत्यु एवं दिव्यांगता बीमा कवर
58+ करोड़ से अधिक नामांकन
समावेशी पात्रता
18-70 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जिनका बैंक या डाकघर में खाता है
कम लागत एवं आसान नवीनीकरण
सिर्फ ₹20 वार्षिक प्रीमियम के साथ ऑटो-डेबिट नवीनीकरण सुविधा

Atal Pension Yojana
गारंटीड मासिक पेंशन
60 वर्ष की आयु के बाद
₹1,000-₹5,000 तक की सुनिश्चित पेंशन
9+ करोड़ से अधिक नामांकन
समावेशी सामाजिक सुरक्षा योजना
18-40 वर्ष आयु के गैर-आयकरदाता बैंक खाताधारकों के लिए खुली
सुरक्षित बचत
सरकार समर्थित पेंशन आश्वासन के साथ लचीला अंशदान

"जन सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से हम सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में किसी भी गरीब व्यक्ति को संकट के समय अपने परिवार के भविष्य की चिंता न करनी पड़े।"
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हमें फॉलो करें | financialservices.gov.in

CBC 15415/13/0003/2627

भाजपा बंगाल के बाद पंजाब में भी 'भय और विभाजन की राजनीति' की पुनरावृत्ति कर रही : मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बठिंडा/भाषा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि अगले होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनाई गई 'भय और विभाजन की राजनीति' को यहां भी दोहराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की इस कोशिश के पीछे की मंशा समुदायों को आपस में बांटकर सत्ता हथियाना है। उन्होंने पंजाबियों से राज्य की शांति, सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव के शत्रु विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि सांप्रदायिक राजनीति को पंजाब के सदियों पुराने भाईचारे को भंग करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अपनी 'शुकराना यात्रा' के तीसरे दिन की शुरुआत बठिंडा से की और तख्त श्री दमदमा साहिब में मत्था टेका।

वह राज्य में लागू किए गए बेअदबी विरोधी कानून के प्रति आभार जताने के लिए चार दिवसीय राज्यव्यापी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। मान ने कहा कि वह ईश्वर के ऋणी हैं, जिन्होंने उन्हें जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 को लागू करके मानवता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। इस अधिनियम में बेअदबी के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। मान ने भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में आजमाई गई वही ''भय और विभाजन की राजनीति'' अब पंजाब में भी दोहराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें समाज का ध्रुवीकरण करने और सत्ता हथियाने के लिए समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने 'पंजाब पंजाबियों का है' का नारा लगाते हुए कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पंजाब के दुश्मन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में विभाजनकारी राजनीति के जरिये सत्ता हासिल की, लेकिन पंजाब में ऐसी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी क्योंकि यहां के लोग हर त्योहार एक साथ मनाते हैं।

पंजाब में मादक पदार्थों की समस्या पर न्यायालय ने जताई चिंता, 'बड़ी मछलियों' को पकड़ने के लिए कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे पर शुक्रवार को चिंता जताई और कहा कि इससे होने वाली मौत के मामले 'खतरनाक' हैं। न्यायालय ने राज्य में नशीले पदार्थों से निपटने के तरीके में बड़े बदलाव की जरूरत बताई।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हाल की एक घटना का ज़िक्र किया जिसमें एक मां ने अपने सभी पांच बेटों को मादक पदार्थ की लत की वजह से खो दिया था।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''देखिए हमने क्या पढ़ा। एक मां रो रही है। उसने अपने पांचवे बेटे को मादक पदार्थों की वजह से खो दिया। उसने अपने सभी बच्चों को नशीले पदार्थों की लत की वजह से खो दिया... पुलिस को संवेदनशील बनाने की जरूरत है।'' पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा उस स्तर पर पहुंच गया है जहां केंद्र सरकार का दखल जरूरी हो सकता है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''शायद केंद्र सरकार के दखल की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन जब वे दखल दें, तो यह न सोचें कि केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है।'' उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने के एक ही लक्ष्य की ओर काम करने को कहा।

उन्होंने कहा, ''साझा लक्ष्य मादक पदार्थों के खतरे को रोकना होना चाहिए।''

पीठ ने राज्य पुलिस से इस बात के लिए भी नाखुशी जताई कि वे 'प्रचार' के लिए छोटे स्तर के अपराधियों पर ध्यान दे रही है, जबकि बड़े तस्करों को खुला छोड़ दिया जा रहा है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ''बड़ी मछलियों या असरदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि लुधियाना ऐसे धंधे का सेंटर है।

पीठ ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज बहुत सारे लंबित मामलों पर भी रोशनी डाली। इससे निपटने के लिए, उसने मुकदमों में तेजी लाने के लिए सभी राज्यों में एनडीपीएस अदालत बनाने में मदद करने का वादा किया।

हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार पानीपत में दुर्घटना में घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार शुक्रवार को पानीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टोल प्लाजा के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विकास एवं पंचायत मंत्री पंवार दुर्घटना के समय एसयूवी में यात्रा कर रहे थे।

जहां दुर्घटना हुई उस क्षेत्र के थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि किसी ने अचानक सड़क पर अपनी कार रोक दी, जिसके कारण मंत्री के काफिले के वाहनों को भी अचानक रुकना पड़ा।

पुलिस ने बताया कि एसयूवी के आगे चल रहे काफिले के वाहन से टकराने के बाद एयरबैग खुल गए।

पुलिस के अनुसार मंत्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कलाई में सूजन और घुटने में दर्द होने के कारण उन्हें पानीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया।

पानीपत के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को फोन पर बताया कि मंत्री ठीक हैं।

पानीपत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय मलिक ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सिर और रीढ़ का सीटी स्कैन सहित कई परीक्षण किए गए और रिपोर्ट सामान्य थीं।

विदेशी मुद्रा भंडार 7.79 अरब डॉलर घटकर 690.69 अरब डॉलर

मुंबई/भाषा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक मई को समाप्त सप्ताह के दौरान 7.79 अरब डॉलर घटकर 690.69 अरब डॉलर रहा। आरबीआई ने यह जानकारी दी। इससे पछले 24 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.82 अरब डॉलर घटकर 698.49 अरब डॉलर रहा था।

इस साल 27 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान, पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने से पहले, यह कोष बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 728.49 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इसके बाद कई हफ्तों तक इसमें गिरावट देखने को मिली। इसका कारण दबाव में आये रुपए को समर्थन देने के लिए रिजर्व बैंक को डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा था। आंकड़ों के मुताबिक, एक मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 2.79 अरब डॉलर घटकर 551.82 अरब डॉलर रही। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में बदलाव का प्रभाव शामिल होता है।

'एनसीआरबी के आंकड़ों ने कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सरकार के खोखले दावों को उजागर किया'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों ने कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर मोदी सरकार के खोखले दावों को उजागर कर दिया है। एनसीआरबी-2024 की रिपोर्ट बीते बुधवार को जारी की गई।

खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मोदी सरकार के 12 वर्षों ने कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर उसके दावों का खोखलापन उजागर कर दिया है और सच्चाई देश के सामने ला दी है।'' उन्होंने कहा, ''एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2013 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध 42.6 प्रतिशत बढ़ गए हैं, बच्चों के खिलाफ अपराध 204.6 प्रतिशत बढ़ गए हैं, दलितों के खिलाफ अत्याचार में 41.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आदिवासियों के खिलाफ अपराध 46.7 प्रतिशत बढ़ गए हैं।''

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''साइबर अपराध में 1,689 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 10,546 किसानों, 52,931 दिहाड़ी मजदूरों और 14,488 छात्रों ने आत्महत्या की।'' अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, ''एनसीआरबी-2024 की रिपोर्ट केंद्र की भाजपा सरकार के महिला सुरक्षा से जुड़े दावों की पोल खोल रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 11 साल में 42,85,888 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सामने आए हैं। भाजपा सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये महिलाएं पिछले कई साल से न्याय मांग रही हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही।'' उन्होंने कहा कि देश में हर 70 मिनट में एक महिला दरिंदगी का शिकार होती है।

टीवीके साथ कांग्रेस का जाना सुविधा की राजनीति, अनैतिक कृत्यः अय्यर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के साथ गठबंधन करने के कांग्रेस के फैसले को शुक्रवार को ''बहुत खराब'' करार दिया और कहा कि यह सुविधा की राजनीति तथा महात्मा गांधी की 1925 के उस कथन का ''अक्षम्य उल्लंघन'' है कि स्वराज का मतलब नैतिकता पर आधारित सरकार होना चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 'पीटीआई-भाषा' के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने टीवीके के विजय को अपने साथ जोड़कर अनैतिक कृत्य किया है और इसमें ''निम्न स्तर के राजनीतिक अवसरवाद'' की बू आती है। उन्होंने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम के साथ चुनाव लड़ने के तुरंत बाद उस टीवीके के साथ गठजोड़ करने का फैसला बहुत खराब है, जिसने ''23 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हराया।'' अय्यर ने कहा, ''यह महात्मा गांधी के 1925 के उस कथन का अक्षम्य उल्लंघन है कि स्वराज को नैतिकता पर आधारित सरकार होनी चाहिए।'' तमिलनाडु के मयिलादुतुरई के पूर्व सांसद ने कहा, ''नवंबर 1925 में लगभग सौ साल पहले, महात्मा गांधी ने अपनी गुजराती पत्रिका 'नवजीवन' में कहा था कि स्वराज का मतलब नैतिकता आधारित सरकार होना चाहिए। चुनाव में टीवीके का विरोध करने के बाद टीवीके के साथ जाने के अपने हालिया फैसले में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के कथन का उल्लंघन किया है।''

एयर इंडिया ने 'मुश्किल समय' में उठाए खर्च घटाने के कदम, वेतन वृद्धि एक तिमाही टली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैंपबेल विल्सन ने शुक्रवार को कर्मचारियों को गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाने और अनावश्यक खर्चों को टालने का निर्देश दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि विल्सन ने इस समय के मुश्किल हालात में एयरलाइन की लागत घटाने की जरूरत पर जोर देते हुए यह निर्देश जारी किया है। साथ ही पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कई चुनौतियों से जूझ रही एयर इंडिया के प्रबंधन ने कर्मचारियों की छंटनी की आशंका से इनकार किया। विल्सन ने एयरलाइन के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) संजय शर्मा और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी रवींद्र कुमार जीपी के साथ कर्मचारियों को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक, रवींद्र कुमार ने कहा कि कंपनी पिछले वित्त वर्ष के लिए 'परिवर्तनीय वेतन' (वेरिएबल पे) जारी रखेगी और तय पदोन्नतियों को भी लागू करेगी। हालांकि अनिश्चित आर्थिक माहौल को देखते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि को कम से कम एक तिमाही के लिए टाल दिया जाएगा।

आईपीएल मैचों में सट्टा खिलाते अंतरराष्ट्रीय गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

देहरादून/भाषा। उत्तराखंड एसटीएफ तथा देहरादून पुलिस ने शुक्रवार को एक संयुक्त कार्रवाई में एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए आईपीएल मैचों में सट्टा लगवाते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है । पुलिस ने यह जानकारी दी ।

देहरादून के पुलिस अधीक्षक (नगर) प्रमोद कुमार ने बताया कि ऑनलाइन सट्टे के लिए इन आरोपियों को प्रतिबंधित रेडीबुक बैटिंग एप का यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध कराने वाला मुख्य अभियुक्त दिल्ली निवासी सुमित यादव है और उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा । कुमार ने बताया कि बसंत विहार की ऋषि विहार कॉलोनी में किराये के एक फ्लैट में ऑनलाइन सट्टा खिलाने की सूचना मिलने पर बृहस्पतिवार रात वहां छापा मारा गया और मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली को बेहतर रूप में विकसित करना सभी की साझा जिम्मेदारीः संधू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी ने हमेशा एक विविधतापूर्ण, लचीले, गतिशील और महत्वाकांक्षी शहर के रूप में भारत की भावना का प्रतिनिधित्व किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में उन्होंने कहा कि दिल्ली के सामने मौजूद चुनौतियों के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

उपराज्यपाल ने शहरीकरण, पर्यावरणीय दबाव, जनसंख्या वृद्धि, आवागमन संबंधी चुनौतियों और संसाधन प्रबंधन को प्रमुख चिंताएं बताते हुए कहा, ''हमारे सामने जो कार्य है वह आसान नहीं है।'' संधू ने कहा, दिल्ली को नए और बेहतर रूप में विकसित करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। आइए, मिलकर एक ऐसी दिल्ली का निर्माण करें जो पर्यावरण के प्रति जागरूक, सांस्कृतिक रूप से जीवंत, आर्थिक रूप से गतिशील, तकनीकी रूप से प्रगतिशील और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हो।'' विश्वविद्यालय के 'स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज' ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की। संधू इसी स्कूल के पूर्व छात्र हैं।

जेएनयू में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि परिसर में लौटना उनके लिए एक बेहद व्यक्तिगत अनुभव है।

प. एशिया संकट से सरकारी तेल कंपनियों को महीने में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान

नई दिल्ली/भाषा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल के बावजूद देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम स्थिर होने की वजह से प्रतिदिन 700-1,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम एशिया संकट के बाद सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसील को प्रतिदिन करीब 700 से 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो मासिक आधार पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए बैठता है। पेट्रोलियम कंपनियों की लागत और खुदरा मूल्य के बीच का अंतर मार्च-अप्रैल में तेजी से बढ़ा है। हालांकि बाद में इसमें कुछ नरमी आई। अप्रैल में पेट्रोल पर करीब 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान होने का अनुमान है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव है और आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल की कीमत दो महीने पहले करीब 70 डॉलर प्रति बैरल थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। शर्मा ने कहा, सरकार का अब तक प्रयास रहा है कि कीमतों को स्थिर रखा जाए और उपभोक्ताओं पर कोई बढ़ोतरी न डाली जाए। इससे तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है। मासिक नुकसान करीब 30,000 करोड़ रुपए पर है। हालांकि, उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें आगे भी स्थिर रहेंगी। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, अब तक प्रयास यही रहा है कि कीमतों में कोई बढ़ोतरी न हो। सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों पर आए दबाव को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती की है।

एआईएमआईएम पार्षद ने टीसीएस मामले की आरोपी निदा खान को शरण दी थी : पुलिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। नासिक पुलिस ने शुक्रवार को दावा किया कि एआईएमआईएम के एक पार्षद ने टीसीएस में कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के मामले में आरोपी निदा खान और उसके परिवार को छत्रपति संभाजीनगर में शरण दी थी।

नासिक पुलिस ने बताया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पार्षद मतीन पटेल से लगातार पूछताछ के बाद बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय संयुक्त पुलिस अभियान में खान को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि पटेल को इस मामले में आरोपी बनाया गया है क्योंकि उन्होंने खान (27) को शरण दी थी, जो आईटी कंपनी की इकाई में नौ महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने वाले गिरोह की एक प्रमुख संदिग्ध है। नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक ने बताया कि खान को बृहस्पतिवार को छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव इलाके से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार और उनकी टीम ने खान की तलाश में नासिक पुलिस की मदद की। संयुक्त अभियान के बारे में कार्णिक ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने वहां खान के ठिकाने का पता लगाया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर, शहर के पुलिस प्रमुख पवार ने पटेल और कुछ अन्य लोगों को नगर निकाय चुनावों के दौरान उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा के शुल्कों की समीक्षा करने के बहाने बुलाया। अधिकारी ने बताया कि जब पटेल पुलिस की सुरक्षा शाखा में पहुंचे, तो पवार ने उनसे पूछताछ की, और लगातार पूछताछ के बाद एआईएमआईएम नेता ने खान और उसके परिवार के ठिकाने का खुलासा किया।

भारत विमानों को पट्टे पर देने में एक प्रमुख केंद्र बनने का इच्छुकः विमानन मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गांधीनगर/भाषा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने शुक्रवार को कहा कि भारत विमानों को पट्टे पर देने वाले वैश्विक लीजिंग केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उनके पूरक के रूप में काम करते हुए मजबूत घरेलू परिवेश विकसित करने पर ध्यान दे रहा है।

नायडू ने यहां गिफ्ट सिटी में आयोजित 'इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.0' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और यह न केवल देश बल्कि आसपास के क्षेत्र को भी सक्षम बना सकता है। उन्होंने कहा, वैश्विक विमान पट्टा बाजार, खासकर भारत से जुड़े हिस्से का आकार इतना बड़ा है कि दुनिया की कई निजी कंपनियां इसका हिस्सा बन सकती हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ते परस्पर जुड़ाव के कारण विभिन्न क्षेत्रीय केंद्र विकसित हो सकते हैं। भारत भी इस क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी बनना चाहता है लेकिन इसके साथ हम मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का पूरक भी बनना चाहते हैं।

नायडू ने बताया कि भारत फिलहाल घरेलू नागर विमानन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और मौजूदा रफ्तार को देखते हुए वैश्विक स्तर पर भी तीसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है। नायडू ने कहा कि देश में वाणिज्यिक विमानों का बेड़ा 2027 तक 1,100 और 2032 तक बढ़कर 2,250 विमान हो जाने की उम्मीद है। वर्ष 2026 में अब तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर यात्री संख्या 19.1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को विमानों को पट्टे पर देने यानी लीजिंग का एक पूर्ण-विकसित वैश्विक केंद्र बनाने की जरूरत है, जहां विमान लीजिंग से जुड़े लेन-देन की संरचना, निष्पादन और प्रबंधन देश के भीतर ही हो।

नायडू ने कहा कि सरकार गिफ्ट सिटी में कानूनी एवं कर सुधारों, विवाद समाधान प्रणाली एवं वित्तपोषण ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकारी प्रयासों के परिणाम भी सामने आए हैं और दिसंबर 2025 तक गिफ्ट आईएफएससी में 38 विमान पट्टा कंपनियां पंजीकृत हो चुकी हैं।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों का संरचनात्मक ऑडिट होगा : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी विद्यालयों का संरचनात्मक ऑडिट कराया जाएगा ताकि उनमें मौजूदा कमियों और सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि गुप्ता ने शुक्रवार को उत्तर दिल्ली के एक सर्वोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था जहां शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने संरचनात्मक ऑडिट कराने का फैसला किया है।

गुप्ता ने बताया, दिल्ली के लगभग 700 स्कूलों में नए भवनों और बड़े स्तर पर पुनर्विकास की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई स्कूलों के भवन 40 से 50 वर्ष पुराने हैं। अब उनकी स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है। उन्होंने कहा, इस ऑडिट के माध्यम से इन स्कूलों के भवनों की मजबूती, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को आदेश जारी किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार को घेरते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने शिक्षा मॉडल का खूब प्रचार किया, लेकिन जमीनी स्तर पर जरूरी काम नहीं किए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अगर पूर्व की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को वास्तव में मजबूत किया होता तो आज बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के लिए शिकायत नहीं करनी पड़ती। केवल विज्ञापन और प्रचार से शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं बनती, बल्कि स्कूलों में वास्तविक सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक होता है।

आईआईटी मद्रास का वैश्विक विस्तार : अमेरिका के मेनलो पार्क में खुला पहला डीप-टेक केंद्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने वैश्विक नवाचार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अमेरिका में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया है। आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में इस केंद्र की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप्स और अनुसंधान को वैश्विक बाजारों से जोड़ना है।

6 मई को 'सेलेक्टयूएसए इन्वेस्टमेंट समिट' के दौरान इस केंद्र की आधिकारिक घोषणा की गई। इस परियोजना में 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। इसमें आईआईटी मद्रास की ओर से 4.5 मिलियन डॉलर का सीधा निवेश शामिल है। इस केंद्र को 24 अप्रैल को 'सीए स्टार्टअप्स' के सहयोग से शुरू किया गया था। आईआईटीएम ग्लोबल के निदेशक प्रोफेसर रघुनाथन रंगास्वामी ने बताया कि पश्चिमी तट (वेस्ट कोस्ट) पर यह उपस्थिति भारत और अमेरिका के बीच नवाचार का एक मजबूत सेतु बनाएगी। वहीं, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामाकोटी ने इसे भारतीय अनुसंधान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने की दिशा में एक स्वाभाविक प्रगति बताया।

आईआईटीएम ग्लोबल के सीईओ थिरुमलई माधवनारायण ने यह केंद्र प्रयोगशाला में किए गए अनुसंधानों को बाजार तक तेजी से पहुंचाने के लिए एक रणनीतिक आधार का काम करेगा। मेनलो पार्क केंद्र मुख्य रूप से डीप-टेक व्यावसायीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही, संस्थान ने अमेरिकी पूर्वी तट पर एक दूसरा केंद्र स्थापित करने की योजना का भी खुलासा किया है, जो वित्तीय और नीतिगत प्रणालियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। यह एक संघीय कार्यक्रम है जो अमेरिका में व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। आईआईटी मद्रास का यह कदम भारत की तकनीकी प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चेन्नई डिवीजन ने स्क्रैप निपटान में 37.2 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया

चेन्नई। दक्षिणी रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्क्रैप निपटान के माध्यम से अब तक की सबसे अधिक कमाई दर्ज करके गैर-किराया राजस्व सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने 11,906 मीट्रिक टन स्क्रैप का निपटान किया, जिसमें पुरानी रेल पटरियां, अनुपयोगी मशीनरी, औजार, लौह और अलौह धातुएं तथा अन्य अप्रचलित रेलवे परिसंपत्तियां शामिल थीं। इससे रिकॉर्ड 37.2 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष के 8,466 मीट्रिक टन स्क्रैप निपटान और 30.3 करोड़ रुपये के राजस्व के प्रदर्शन को पीछे छोड़ देता है।

यह उपलब्धि स्क्रैप निपटान की मात्रा में 40 प्रतिशत से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व में लगभग 7 करोड़ रुपये की वृद्धि को दर्शाती है, जिससे डिवीजन के लिए स्क्रैप प्रबंधन और संसाधन अनुकूलन में एक नया मानदंड स्थापित होता है। यह रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन निरंतर निगरानी, स्क्रैप सामग्री की व्यवस्थित पहचान और पृथक्करण, पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रियाओं के माध्यम से समय पर निपटान और प्रभाग के विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के कारण संभव हुआ। स्क्रैप निपटान अभियान को तेज करने से रेलवे की बहुमूल्य जगह खाली हुई है, स्वच्छता मानकों में सुधार हुआ है और रेलवे परिसर में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। चेन्नई डिवीजन परिचालन दक्षता बढ़ाने और गैर-किराया राजस्व में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक स्क्रैप प्रबंधन पद्धतियों और प्रभावी परिसंपत्ति उपयोग पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस दिशा में डिवीजन की सक्रिय पहलों ने टिकाऊ रेलवे संचालन और बेहतर अवसंरचना प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

तमिलनाडु में राजनीतिक संकट से जुड़े रणनीतिक फैसले केंद्रीय नेतृत्व लेगा : नवनिर्वाचित भाजपा विधायक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु से भाजपा के एकमात्र निर्वाचित विधायक भोजराजन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार गठन और तमिलनाडु में मौजूदा राजनीतिक संकट से संबंधित सभी प्रमुख रणनीतिक निर्णय उनकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए जाएंगे। गठबंधन सरकार की संभावना या मौजूदा अस्थिरता में भाजपा की विशिष्ट भूमिका के बारे में पूछे जाने पर, भोजराजन ने पार्टी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कोई सीधा जवाब नहीं दिया।

उन्होंने कहा, ''नहीं, नहीं, नहीं। इन सब बातों का फैसला हमारे मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।'' संपर्क संबंधी खामियों और सरकार गठन पर भाजपा के रुख के बारे में पूछे गए सवाल पर उधगमंडलम के नवनिर्वाचित विधायक ने दोहराया, ''ये नीतिगत निर्णय हैं। मैं इन पर टिप्पणी नहीं कर सकता; इन मामलों पर केवल आलाकमान ही निर्णय लेता है।''

पार्टी के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि आंकड़े उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं हैं। अपनी जीत के बारे में उन्होंने कहा, मैं बेहद खुश हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे और भी खुशी होती अगर भाजपा से और अधिक सदस्य निर्वाचित होते। नवनिर्वाचित विधायक ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि वह पिछले पांच वर्षों में देखी गई विकास की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा, ''मुझे अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैंने अपने घोषणापत्र में कई वादे किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वे पूरे किए जा सकते हैं। पिछले पांच वर्षों में कुछ खास नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम करूंगा।''

सरकार गठन के लिए टीवीके को मिला वाम दलों का समर्थन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में नयी सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या बल जुटाने का प्रयास कर रही विजय की पार्टी टीवीके शुक्रवार को वाम दलों का समर्थन मिल जाने से साधारण बहुमत के लिए जरूरी 118 के जादुई आंकड़े के काफी करीब पहुंच गई। तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल दोनों वामपंथी दलों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने कहा कि यह (समर्थन देने का) निर्णय भाजपा को राज्य में पिछले दरवाजे से 'प्रवेश'' करने से रोकने के लिए लिया गया है। हालांकि, राज्य के अधिकारों के मामले में वे (वाम दल) द्रमुक के साथ बने रहेंगे। वाम दलों ने घोषणा की कि वे टीवीके मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे।

भाकपा और माकपा, दोनों के दो-दो विधायक हैं। उन्होंने दिनभर की चर्चा के बाद अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी को अपना समर्थन देने की घोषणा की। उनके समर्थन के साथ, टीवीके प्रमुख आज बाद में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने के अपने दावे को दोहराएंगे। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की 108 सीटें हैं, लेकिन यह बहुमत के आंकड़े से 10 कम है।

टीवीके ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सहयोगी दलों माकपा, भाकपा और विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) से संपर्क किया था तथा 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन मांगा था। भाकपा, माकपा और वीसीके, प्रत्येक के दो-दो विधायक हैं। एक ओर जहां भाकपा ने शुरुआत में तमिलनाडु के राज्यपाल को टीवीके को समर्थन देने के अपने फैसले की सूचना दी, वहीं माकपा ने भी कुछ

ही समय बाद अपने सहयोगी दल का अनुसरण किया, जिससे विजय की पार्टी साधारण बहुमत के काफी करीब पहुंच गई। वाम दलों ने राज्यपाल को संबोधित पत्र में टीवीके को अपना समर्थन देने की जानकारी दी। पांच विधायकों वाली कांग्रेस ने पहले ही टीवीके को समर्थन दे दिया है। विधानसभा चुनावों में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, पार्टी संस्थापक विजय को अपनी जीती हुई दो सीटों में से एक को छोड़ना होगा। विजय को चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व सीटों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। उनके ऐसा करने की स्थिति में टीवीके और उसका समर्थन कर रहे विधायकों की कुल संख्या अब 116 हो गई है। ऐसे में, विजय को अपनी पहली सरकार बनाने के लिए अब दो और विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है और दो विधायकों वाली वीसीके इस संबंध में शनिवार को अपना रुख सार्वजनिक करने वाली है। इस बात की प्रबल संभावना है कि वह वामपंथी दलों का अनुसरण कर सकती है। इस बीच, एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, विजय शुक्रवार शाम को राज्यपाल आर्लेकर से सरकार गठन के संबंध में मुलाकात करेंगे। सरकार बनाने के दावे को लेकर राज्यपाल के साथ यह उनकी तीन दिनों में तीसरी मुलाकात होगी। टीवीके के एक सूत्र ने बताया कि राज्यपाल के साथ बैठक के दौरान विजय संभवत: सरकार बनाने के अपने दावे को दोहराएंगे। माकपा के प्रदेश सचिव पी. शनमुगम और भाकपा के प्रदेश सचिव एम. वीरपांडियन ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। शनमुगम ने कहा कि टीवीके को समर्थन देने का निर्णय भाजपा के तमिलनाडु में पिछले दरवाजे से ''प्रवेश'' को रोकने के लिए लिया गया है। इसका उद्देश्य भाजपा के चुनाव हारने के बावजूद राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर शासन करने के प्रयास को रोकना है। उन्होंने कहा, अगर 10 दिनों के भीतर सरकार का गठन नहीं हुआ, तो राज्यपाल शासन लागू करना पड़ सकता है। राज्य के अधिकारों की रक्षा के मामले में वामपंथी दल द्रमुक के साथ गठबंधन में बने रहेंगे। भाकपा, माकपा और वीसीके ने द्रमुक के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) के घटक के तौर पर चुनाव लड़ा था।

माकपा नेता शनमुगम ने भविष्य में होने वाले चुनावों में वामपंथी पार्टियां किस दल के साथ चुनावी गठबंधन करेंगी, इससे संबंधित सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। इस बीच, वीसीके ने कहा कि वह टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर चर्चा के लिए शुक्रवार शाम डिजिटल माध्यम से एक बैठक की। उन्होंने कहा, ''मैं कल (शनिवार) सुबह औपचारिक रूप से प्रेस को संबोधित करके अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करूंगा।'' उनसे जब अन्नाद्रमुक के नेतृत्व में सरकार गठन की पहल में, वीसीके के समर्थन की संभावना के बारे में पूछा गया, तो थिरुमावलवन ने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया और ऐसे परिदृश्यों को ''काल्पनिक'' बताया।

हम तमिलनाडु के जनादेश का सम्मान करते हैं, नई सरकार में शामिल नहीं होंगे : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई ने शुक्रवार को कहा कि वह राज्य के लोगों की इच्छा और जनादेश का सम्मान करती है और नई सरकार बनाने की किसी भी कोशिश में शामिल नहीं होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि पार्टी इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहती और सरकार बनाने में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देगी। विधानसभा चुनाव परिणाम के चार दिन बाद, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों की भलाई और तरक्की के लिए प्रतिबद्ध भाजपा ने चुनाव में पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया था।

नागेंद्रन ने यहां एक बयान में कहा, ''हालांकि, चुनाव परिणामों को हमारी पार्टी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है और हमें लगता है कि तमिलनाडु के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जनादेश नहीं दिया है।'' तमिलनाडु में भाजपा के खाते में सिर्फ एक सीट आई है।

उन्होंने कहा, ''हम तमिलनाडु के लोगों की इच्छा और जनादेश का दिल से सम्मान करते हैं और तमिलनाडु राज्य में नई सरकार बनाने की किसी भी कोशिश में शामिल नहीं होना चाहते। इसलिए, हम इस प्रक्रिया में कोई सक्रिय भागीदारी नहीं चाहते।''

अन्नाद्रमुक प्रमुख पलानीस्वामी ने पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में तमिलनाडु के पार्टी विधायकों के साथ बैठक की

पुडुचेरी। अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु से नवनिर्वाचित विधायकों के साथ पुडुचेरी के बाहरी इलाके अरियानकुप्पम के पास स्थित एक निजी रिसॉर्ट में बैठक की। करीब 40 विधायक इस बैठक में मौजूद थे, जो लगभग एक घंटे तक चली। पार्टी सूत्रों के अनुसार, पलानीस्वामी ने नवनिर्वाचित विधायकों से एकजुट रहने और धैर्य बनाए रखने को कहा।

उन्होंने विधायकों से कहा, ''अच्छी चीजें होंगी, इसलिए आप सभी अगले कुछ दिनों तक रिसॉर्ट में एकजुट रहें और धैर्य बनाए रखें।'' यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पहले ही टीवीके को समर्थन दे चुकी है, जिसके पास पांच विधायक हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीतीं, जबकि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को 59, अन्ना द्रमुक को 47, कांग्रेस को पांच, पीएमके को चार, आईयूएमएल को दो, भाकपा को दो, माकपा को दो और वीसीके को दो सीटें मिलीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), डीएमडीके और एएमएमके को एक-एक सीट मिली। टीवीके प्रमुख विजय को जीती गई दो सीटों में से एक सीट से इस्तीफा देना होगा। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके 118 विधायकों के समर्थन के आंकड़े तक पहुंचने से पीछे रह गई।

टीवीके ने न्यायालय का किया रुख, सरकार गठन के लिए न्योता देने का राज्यपाल को निर्देश देने का आग्रह

नई दिल्ली/चेन्नई। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार गठन के लिए न्योता देने का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। राज्य में 23 अप्रैल को हुए चुनावों में, टीवीके 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। टीवीके के संस्थापक विजय ने राज्यपाल से अब तक दो बार मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए उन्हें न्योता देने का अनुरोध किया है। हालांकि, अभी तक नवगठित पार्टी को ऐसा कोई न्योता नहीं भेजा गया है। शुक्रवार शाम को विजय ने राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात की।

टीवीके शीघ्र ही सरकार बनायेगी : मायलापुर के नवनिर्वाचित विधायक वेंकटरमनन

चेन्नई। मायलापुर के नवनिर्वाचित टीवीके विधायक पी वेंकटरमनन ने तमिलनाडु में सरकार गठन की पार्टी की क्षमता पर शुक्रवार को पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए आवश्यक संख्या बल है। सरकार गठन को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच उन्होंने यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में पार्टी के पास बहुमत न होने की चिंताओं को खारिज कर दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या पार्टी ने स्थिर सरकार के लिए आवश्यक निश्चित आंकड़े हासिल कर लिए हैं, तो उन्होंने दृढ़ता से 'हां' में जवाब दिया।

तमिलनाडु में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित, उत्तीर्ण प्रतिशत 95.03 रहा

चेन्नई। तमिलनाडु में शुक्रवार को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें राज्य का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.03 दर्ज किया गया। यह पिछले वर्ष के 95.03 प्रतिशत की तुलना में 0.17 प्रतिशत अधिक है।

परिणाम जारी करते हुए यहां स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इरोड जिले का उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक 98.87 दर्ज किया गया, जबकि शिवगंगा जिला 98.05 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं 95.43 प्रतिशत उत्तीर्णता के साथ चेन्नई रैंकिंग में 20वें स्थान पर रहा।

इस वर्ष लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 97 रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत केवल 93.19 प्रतिशत दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 7,536 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 2,639 निजी स्कूलों और 489 सरकारी स्कूलों ने 100 प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। कुल 7,91,654 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 7,53,694 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए। विज्ञान संकाय का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 96.90 रहा, जबकि वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.67 दर्ज किया गया।

संतोष ने तमिलनाडु को लेकर कांग्रेस पर तंज किया, टैगोर ने किया पलटवार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संगठन महामंत्री बी एल संतोष ने तमिलनाडु के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार कोई भी बनाए, लेकिन अंत में देश के मुख्य विपक्षी दल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।

इस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा विधायकों को ''खरीदने'' के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है और उसे जरूर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी क्योंकि तमिलनाडु की जनता विजय और कांग्रेस के साथ है।

संतोष ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''तमिलनाडु में कौन सरकार बनाएगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है कि अंत में कांग्रेस को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी।'' लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक टैगोर ने उनके पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी और तमिलनाडु के लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया कि विजय मुख्यमंत्री होंगे।

उन्होंने कहा, ''भाजपा समय जाया करने और विधायकों को 'खरीदने' के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है। चिंता न करें, लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे (भाजपा) खरीदारों को शर्मिंदगी जरूर झेलनी पड़ेगी।'' तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पहले ही टीवीके को समर्थन दे चुकी है, जिसके पास पांच विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीतीं, जबकि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को 59, अन्ना द्रमुक को 47, कांग्रेस को पांच, पीएमके को चार, आईयूएमएल को दो, भाकपा को दो, माकपा को दो और वीसीके को दो सीटें मिलीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), डीएमडीके और एएमएमके को एक-एक सीट मिली। टीवीके प्रमुख विजय को जीती गई दो सीटों में से एक सीट से इस्तीफा देना होगा।

दक्षिणी रेलवे के लिए नए प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां ए. नारायणन, आईआरपीएस ने 8 मई को दक्षिणी रेलवे के नए प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पदभार ग्रहण करने से पहले, वे दक्षिणी रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन के पद पर कार्यरत थे। ए. नारायणन, जो भारतीय रेल कार्मिक सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं, ने अपने रेल करियर की शुरुआत असम के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग डिवीजन में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में की।

अपने विशिष्ट करियर के दौरान, उन्होंने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तिनसुकिया डिवीजन में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिणी रेलवे के चेन्नई डिवीजन में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिणी रेलवे में उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित, दक्षिणी रेलवे के एम्मोर में उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण, रेलवे भर्ती बोर्ड, चेन्नई के सदस्य सचिव और दक्षिणी रेलवे में मुख्य कार्मिक अधिकारी/औद्योगिक संबंध सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। ए. नारायणन ने वडोदरा स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज और जमशेदपुर स्थित एक्सएलआरआई में व्यापक पेशेवर व नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त किया है; साथ ही आईआईएम बेंगलूरु के एमबीए कार्यक्रम के तहत अमेरिका के सिरैक्यूज विवि में; हाई-स्पीड रेल प्रशिक्षण के लिए चीन के चेंगदू स्थित साउथवेस्ट जियाओतोंग विवि में; सिंगापुर स्थित आईएनएसईएडी में; और मलेशिया के कुआलालंपुर स्थित आईसीएलआईएफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस सेंटर में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

राज्यपाल की कोई जरूरत नहीं : द्रमुक नेता कनिमोई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में खंडित जनादेश के बाद सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता के बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की वरिष्ठ नेता कनिमोई ने शुक्रवार को राज्यपाल पद के प्रति पार्टी विरोधी रुख को दोहराया। कनिमोई ने पीटीआई-वीडियो' के साथ बातचीत में कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति के दौरान संबंधित विषय के संवैधानिक औचित्य पर उठ रहे सवालों के मद्देनजर राज्यपाल पद को समाप्त करने की द्रमुक की मांग नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा, हमारा यह रुख है कि हमें राज्यपाल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और द्रमुक का यह रुख कभी नहीं बदलेगा।

कनिमोई ने चुनाव परिणामों के बाद राज्यपाल के कदम, विशेष रूप से सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में देरी के बारे में पूछे जाने पर राज्यपाल पद और राज्य के राजनीतिक हितों के बीच ''अंतर्निहित टकराव'' की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ''मौजूदा स्थिति कई सवाल खड़े करती है'' और संवैधानिक प्रक्रियाओं के संबंध में आत्मावलोकन की आवश्यकता है। कनिमोई ने चुनाव परिणामों को ''स्पष्ट जनादेश'' का अभाव बताया। उन्होंने इसे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता का मुख्य कारण करार दिया। द्रमुक की वरिष्ठ नेता ने कहा, ''जनता का फैसला सर्वोपरि है और यह जनादेश निर्णायक नहीं है, फिर भी इसका सम्मान किया जाना चाहिए।'' थूथुकुडी से सांसद ने किसी भी दल को निर्णायक बहुमत न मिलने को सरकार के गठन में जारी देरी और ''कई भ्रमों'' का कारण बताया।

सरकार गठन के लिए टीवीके को मिली समयसीमा खत्म होने के बाद विकल्पों पर विचार करेंगे : द्रमुक

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता टीकेएस एलंगोवन ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु में राज्यपाल की ओर से अभिनेता-नेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के लिए सरकार गठन के वास्ते निर्धारित समयसीमा के समाप्त होने के बाद ही पार्टी वैकल्पिक सियासी कदमों पर विचार करेगी। चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में एलंगोवन ने कहा कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने टीवीके को यह साबित करने के लिए 10 मई तक की मोहलत दी है कि वह राज्य में सरकार बनाने में सक्षम है। उन्होंने राज्य में मौजूदा राजनीतिक गतिरोध के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। राज्यपाल ने 10 मई तक का समय दिया है। उसके बाद ही हम किसी अन्य योजना के बारे में सोच सकते हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
खेल विभाग / DEPARTMENT OF SPORTS
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय)
(मानव संसाधन प्रभाग -II)
ईस्ट गेट संख्या-10, जे. एन. स्टेडियम परिसर,
लोदी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003

01-04001(03)/11/2025-भर्ती प्रकोष्ठ/251 दिनांक : 10-04-2026

संशोधन सूचना
(शुद्धिपत्र)

विषय: खेल प्राधिकरण, भारत में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक निदेशक (ओएल) के पद पर नियुक्ति।

भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (एमवायएएस) के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है। विज्ञापन संख्या 01-04001(03)/11/2025-रिक्रूटमेंट सेल/183 दिनांक 25-02-2026 के क्रम में, सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर **अब 10-06-2026 (सायं 05:00 बजे तक)** कर दिया गया है। अन्य सभी शर्तें एवं प्रावधान यथावत एवं अपरिवर्तित रहेंगे।

एसएआई एक स्वायत्त निकाय है, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन है तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। संबंधित विज्ञापन संख्या 01-04001(03)/11/2025-भर्ती प्रकोष्ठ/183 दिनांक 25-02-2026 के क्रम में, सहायक निदेशक (ओएल) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को यहां द्वारा 10-06-2026 (सायं 05:00 बजे तक) तक बढ़ा दिया गया है। शेष सभी प्रावधान/शर्तें यथावत एवं अपरिवर्तित रहेंगे।

उप निदेशक (मानव संसाधन प्रभाग -II)
भारतीय खेल प्राधिकरण

CBC 47103/11/0008/2627

रणथंभौर में घूम रहे चीते को वापस मध्यप्रदेश भेजा गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र के एक वन क्षेत्र में घूम रहे चीते को शुक्रवार को वन अधिकारियों ने बेहोश (ट्रेंकुलाइज) कर सुरक्षित रूप से मध्यप्रदेश वापस भेज दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार अनुसार यह काम कूनो राष्ट्रीय उद्यान की टीम, राजस्थान वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव विशेषज्ञों ने निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संयुक्त रूप से किया। अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश से यहां आए इस चीते की गतिविधियों पर पिछले कई दिनों से लगातार नजर रखी जा रही थी जिसके बाद विशेषज्ञों ने उसे 'ट्रेंकुलाइज' करने का फैसला किया।

उप वन संरक्षक मानस सिंह ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया अनुभवी वन्यजीव पशु चिकित्सकों और तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में सुरक्षित रूप से पूरी की गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि चीते को किसी तरह कोई नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि चीते को सुरक्षित रूप से मध्यप्रदेश ले जाया गया।

महात्मा फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक जागरूकता में सक्रिय भागीदारी निभाएं युवा : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को युवाओं से आह्वान किया कि वे महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक जागरूकता में सक्रिय भागीदारी निभाएं। वह यहां महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि समाज सुधार एवं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा की अलख जगाई तथा सामाजिक जागरूकता को नई दिशा दी। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी महिला शिक्षा, सशक्तीकरण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरन्तर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से महात्मा फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

एक सरकारी बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि महात्मा फुले की 200वीं जयंती पूरे देश में दो वर्ष तक मनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस उत्सव को धूम-धाम से मना रही है तथा उसने हिंडौली में महात्मा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय निर्माण का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर प्रखंड में सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी तथा समस्त जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय स्थापना का फैसला किया गया है तथा 16 सावित्री बाई फुले छात्रावास के नये भवनों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 23 से 25 मई तक यहां 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026' का आयोजन करेगी। उन्होंने आमजन को इस आयोजन से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के किसान को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लक्ष्य के साथ निरन्तर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने जाजोद गांव में ग्रामीणों के हाल जाने

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को सीकर के जाजोद गांव में देर तक रात्रि चौपाल लगाई जबकि शुक्रवार सुबह वह गांव की पैदल यात्रा पर निकले और ग्रामीणों के हाल जाने। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पी और संवाद किया। मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार सुबह गांव के भ्रमण पर निकले। लोग घरों से निकले तो उन्होंने सड़क पर मुख्यमंत्री को गांव में टहलते हुए पाया। गांव की गलियों में सहजता के साथ भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, पशुपालकों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं तथा युवाओं से संवाद किया और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया।

प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस दौरान गांव में स्थित गोपीनाथ जी मंदिर एवं शिव मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पी और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर डिजिटल 'लेनदेन' को भी प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से स्थानीय फसलों, कृषि उत्पादों एवं खेती की पारंपरिक पद्धतियों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और नवाचारों के माध्यम से किसान अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीणों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। यमुना जल समझौते को प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए शर्मा ने कहा कि यह समझौता भविष्य में जल संकट के समाधान तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है तथा राज्य सरकार विरासत संरक्षण के लिए हवेलियों के जीर्णोद्धार एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में निरंतर काम कर रही है।

जयपुर में निजी अस्पताल व डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजधानी जयपुर के निजी अस्पताल और डॉक्टर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और आपातकालीन सहित अन्य सेवाएं बंद कर दीं। चिकित्सक संगठनों का आरोप है कि जेल में बंद डॉक्टर सोनदेव बंसल की जमानत याचिका से जुड़ी सुनवाई के दौरान, बृहस्पतिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में उनके परिवार के सदस्यों के साथ अभद्रता व मारपीट की गई।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की जयपुर शाखा सहित विभिन्न चिकित्सा संगठनों ने बृहस्पतिवार रात कार्य बहिष्कार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे राज्य के डॉक्टरों में डर और गुस्सा है। संगठनों के अनुसार बंसल की जमानत याचिका पर कल राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान वकीलों के समूह ने कथित तौर पर नारेबाजी की और अदालत में हंगामा किया जिसके चलते इस मामले की सुनवाई 11 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

डॉक्टरों के संगठनों ने आरोप लगाया कि सुनवाई के बाद बंसल के पिता और भाई को रोका गया और एक बार रूम में ले जाया गया जहां उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया, उनके साथ गाली-गलौज की गई और मारपीट की गई। यह विवाद सितंबर 2025 में जयपुर के एक निजी अस्पताल में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज के दौरान एक वकील की मां मौत के बाद शुरू हुआ।

डॉक्टरों के संगठनों ने दावा किया कि मेडिकल बोर्ड ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं पाई लेकिन बाद में इस योजना से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर बंसल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने बंसल के लिए तत्काल न्याय दिलाने, न्यायिक कार्रवाई में बाधा डालने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और डॉक्टरों तथा उनके परिवारों के लिए सुरक्षा की मांग की है।

नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सामान्य प्रशासन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की।

जैन ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हमें प्रभावी समाधान की ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी, जिससे शिकायतों का निस्तारण संबंधित स्तर पर ही व्यवस्थित रूप से हो सके। प्रमुख शासन सचिव ने निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए सही मैपिंग,श्रेणीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकतम उपयोग करते हुए सही निस्तारण किया जाए।

प्रमुख शासन सचिव ने पोर्टल पर दर्ज नागौर हवाई पट्टी पर अतिक्रमण के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बैठक के दौरान ही नागौर कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की तथा नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जैन ने झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव होने के नाते जिले की परिवेदनाओं का भी विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने जिले के परिवादियों कामिल, धर्मवीर, सुनील, ललित एवं राहुल से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।इस अवसर पर दाताराम, संयुक्त शासन सचिव एवं स्टेट नोडल आफिसर संपर्क पोर्टल सामान्य प्रशासन विभाग एवं हर्ष सावन सूखा, निदेशक, पब्लिक सर्विसेज एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग भी उपस्थित रहे।

एनडीआरएफ सदस्य डॉ. असवाल ने राज्य में आपदा तैयारी एवं आपदा जोखिम वित्तपोषण व्यवस्थाओं की समीक्षा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरएफ) के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन में राहत एवं बचाव के साथ-साथ पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, जनजागरूकता एवं त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया 10 सूत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा सभी प्रकार की आपदाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य कर रहा है।

डॉ. असवाल गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। बैठक में डॉ. असवाल ने शहरी बाढ़, अग्नि सुरक्षा, औद्योगिक आपदाओं, लू प्रबंधन, सिलिकोसिस प्रबंधन, परमाणु एवं विकिरण आपदा तैयारी, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की तैयारियों तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग भास्कर ए. सावंत सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। समस्त जिला कलेक्टर विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

डॉ. असवाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की प्रकृति तेजी से बदल रही है। ऐसे में जिला स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, पूर्व चेतावनी प्रणाली, राहत संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय समन्वय को और अधिक मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रिया स्थानीय स्तर पर होती है, इसलिए जिला प्रशासन, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों को और अधिक सक्षम बनाना आवश्यक है।

उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों, मॉल, कोचिंग संस्थानों एवं औद्योगिक इकाइयों में नियमित मॉक ड्रिल, अग्नि सुरक्षा ऑडिट एवं आपदा प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए वार्षिक सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं तथा ऑफसाइट अभ्यास को वार्षिक कैलेंडर में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। डॉ. असवाल ने सिलिकोसिस प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खनन एवं पत्थर उद्योग क्षेत्रों में जागरूकता, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन भास्कर ए. सावंत ने बताया कि राज्य में आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान, लू, तापघात, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि एवं अग्नि दुर्घटनाएं प्रमुख आपदाएं हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले वर्षों में अत्यधिक वर्षा एवं चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चुनौतियां बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि गत पांच वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को लगभग 3545 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश में जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों, पूर्व चेतावनी प्रणाली, राहत प्रबंधन एवं त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतिक चंद्रशेखर ने अग्नि जोखिम प्रबंधन एवं शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा तैयारियों पर प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 221 अग्निशमन केंद्र एवं 708 अग्निशमन वाहन संचालित हैं। उच्च भवनों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए विभिन्न शहरों में उच्च क्षमता वाले हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने अस्पतालों, स्कूलों, मॉल एवं औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित अग्नि सुरक्षा परीक्षण एवं मॉक ड्रिल आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

आरपीएससी ने विवादों में एसआई भर्ती-2021 परीक्षा निरस्त की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने लंबे समय से विवादों में घिरी रही 'उपनिरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2021' को निरस्त करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग यह परीक्षा फिर से करवायेगी। उन्होंने कहा कि आयोग ने राज्य सरकार की अनुशंसा और अदालत के फैसले के आधार पर यह निर्णय लिया है।

आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि 859 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी और दोबारा होने वाली परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार बैठने के पात्र होंगे जो 2021 की परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या लगभग 3.83 लाख है जो 2021 में 13 से 15 सितंबर तक आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों पेपरों में शामिल हुए थे। साहू ने कहा कि उम्मीदवारों को अपने पहले से जमा किए गए आवेदन पत्रों में सुधार और उन्हें अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुधार के लिए आनलाइन विकल्प 16 मई से 30 मई तक खुला रहेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरान, उम्मीदवार अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता और पत्राचार का पता जैसी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र में कोई भी बदलाव करने से पहले उम्मीदवारों के लिए अपने 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (ओटीआर) में 'केवाईसी' प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 'ओटीआर' से उम्मीदवार की लाइव तस्वीर, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपने आप आवेदन पत्र में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों की 'ओटीआर' में 'केवाईसी' प्रक्रिया अधूरी है उन्हें सुधार करने से पहले इसे पूरा करना होगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पिछले साल अगस्त में एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने का आदेश दिया था। इस साल अप्रैल में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। चयनित प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों (एसआई) ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। हांलाकि, उच्चतम न्यायालय ने हाल में उनकी 'विशेष अनुमति याचिका' (एसएलपी) को खारिज कर दिया। इस परीक्षा के दौरान 'डमी उम्मीदवारों' का इस्तेमाल करने और अन्य अनुचित साधनों का सहारा लेने के आरोप में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने कई प्रशिक्षु एसआई को गिरफ्तार किया था।

किसान की मजबूती से गांव, प्रदेश और देश बनेगा खुशहाल : भजन लाल शर्मा

जयपुर/दक्षिण भारत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीकर जिले में खण्डेला के ग्राम जाजोद में ग्राम विकास चैपाल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब किसान मजबूत होगा तो गांव, प्रदेश और देश खुशहाल बनेगा। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान और आर्थिक सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत एवं आधुनिक खेती को अपनाएं। हमारी सरकार ने किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपये की सम्मान निधि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है और इसे आगे भी बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पशुपालकों को मजबूत बनाने के लिए गोपाल

क्रेडिट कार्ड योजना की सौगात दी है। पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट की सुविधा शुरू की है। किसानों को बीज किट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आधुनिक खेती के तरीके सीखने के लिए कृषि पर्यवेक्षकों से संपर्क स्थापित करें। मृदा का परीक्षण करवाएं, ग्रीन हाउस खेती को अपनाएं।

उन्होंने कहा कि किसानों की सिंचाई जरूरतों की पूर्ति के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों को गति प्रदान की है। वहीं, शेखावाटी क्षेत्र के लिए युमना जल समझौता किया है, जिसे मूर्त रूप देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंगनहर के लिए पर्याप्त बजट दिया है। पूरे प्रदेश में किसानों की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। किसान पीएम कुसुम योजना से जुड़कर अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बने। प्रदेश जीरा, ईसबगोल, सरसों, धनिया जैसी फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसलों से जुड़ी प्रोसेसिंग यूनिट खुलने से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बनेगा। सहकारिता क्षेत्र को भी मजबूत बनाया जा रहा है, नवीन पैक्स खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया। अब तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। जिससे युवाओं को रोजगार मिलने की राह आसान हुई है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रही है। पेपरलीक के आरोपियों को पकड़ा गया है। अब तक सवा लाख से अधिक पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला भी बने। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों और वार्डों के विकास के लिए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान चलाया गया है। जिसके जरिए विकास का रोडमैप बनाया जाएगा।

किसान समृद्ध होंगे तो गांव और देश बनेगा खुशहाल : जवाहर सिंह बेढ़म

जयपुर/दक्षिण भारत। राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को धौलपुर के ग्राम धनौरा में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में किसानों, पशुपालकों एवं ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि किसान मजबूत होगा तो गांव, प्रदेश और देश स्वतः समृद्ध और खुशहाल बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया है तथा भविष्य में इसे 12 हजार रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने किसानों से आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि कृषि पर्यवेक्षकों से संपर्क कर नई तकनीकों की जानकारी लें, मृदा परीक्षण करवाएं तथा ग्रीन हाउस खेती, जैविक खेती और वर्मी कम्पोस्ट जैसी उन्नत पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन और आय दोनों बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बीज किट उपलब्ध करा रही है और कृषि संयंत्रों पर अनुदान भी दिया जा रहा है।

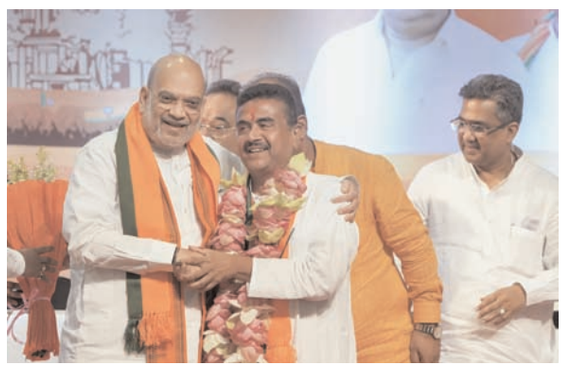

भाजपा सरकार में बंगाल में घुसपैठ, मवेशी तस्करी असंभव हो जाएगी : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल का नेता और मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुने जाने की घोषणा करने के बाद कहा कि राज्य में घुसपैठ और मवेशियों की तस्करी 'नामुमकिन' हो जाएगी।

यहां भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि बंगाल में भारी जीत सिर्फ संगठन का विस्तार या विचारधारा की पुष्टि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक बहाली से जुड़ा जनादेश है। उन्होंने कहा, ''यह जीत हमारे संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के बारे में नहीं है, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ी कमी को ठीक करने के बारे में है... अब पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और गो-तस्करी नामुमकिन हो जाएगी।''पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस शासन पर तीखा हमला करते हुए, शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के दौरान राज्य में ''प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण'' हुआ था। उन्होंने कहा, ''भाजपा के शासन के दौरान, न तो प्रशासन का राजनीतिकरण होगा, न ही राजनीति का अपराधीकरण होगा।''

शाह ने पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित विधायकों की एकमत से मंजूरी का हवाला देते हुए अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता घोषित किया। शाह ने कहा, विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आठ प्रस्ताव मिले थे और उन सभी में सिर्फ एक नाम था। दूसरे नाम के लिए काफी समय दिया गया था, लेकिन कोई दूसरा नाम प्रस्तावित नहीं किया गया। इसलिए, मैं शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री घोषित करता हूं। अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से पश्चिम बंगाल में पहली भाजपा सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल की और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल का राज खत्म हो गया। शाह ने भाजपा का साथ देने के लिए बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा किया, वहीं आरोप लगाया कि राज्य में दशकों से डर और राजनीतिक हिंसा का माहौल था। उन्होंने कहा, मैं बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हू। कम्युनिस्ट जमाने से यहां जो माहौल बना था, वह ममता जी के राज में और बढ़ गया।

घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे : शुभेंदु अधिकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल में 'डर के युग' के समाप्त होने की घोषणा करते हुए राज्य के नामित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नई और पहली भाजपा सरकार सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर काम करेगी, पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए अधिकारी ने आने वाली सरकार की प्राथमिकताएं रेखांकित कीं और कहा कि बंगाल में डर का माहौल खत्म हो गया है और राज्य अब भरोसे के दौर की ओर बढ़ेगा।

पार्टी विधायकों और समर्थकों की ज़ोरदार तालियों के बीच अधिकारी ने कहा, भय अब खत्म हो गया है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है, भरोसा आ गया है। इससे पहले 55 वर्षीय भाजपा नेता को शाह और प्रदेश में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे उनके पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। अधिकारी ने कहा, ''मैं नहीं, बल्कि हम- भाजपा सरकार सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर काम करेगी।'' उन्होंने कहा, ''बंगाल की जनता ने हमें ऐतिहासिक जनादेश दिया है। हम बंगाल में भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे।'' उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की नई भाजपा सरकार के बीच समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। अधिकारी ने कहा, ''केंद्र और बंगाल की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने दें।''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुनावी गारंटियों का उल्लेख करते हुए अधिकारी ने कहा कि जनता से किया गया हर वादा चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपों में जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा, ''एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला आयोग भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच करेगा।

बीपीएससी 'टीआरई-4' परीक्षा में देरी के विरोध में प्रदर्शनरत विद्यार्थियों पर पुलिस का बल प्रयोग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-4 की अधिसूचना जारी करने में हो रही देरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को तितर-बितर करने के लिए पटना पुलिस ने शुक्रवार को बल प्रयोग किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पटना के पुलिस अधीक्षक (एसपी-मध्य) दीक्षा ने कहा, ''प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया।'' हालांकि, विद्यार्थियों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-4 के अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में पटना महाविद्यालय से विरोध मार्च निकाला था और वे डाकबंगला चौराहा की ओर बढ़ रहे थे, इसी दौरान गांधी मैदान के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बिहार में बीपीएससी टीआरई-4 परीक्षा के माध्यम से 46 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की उम्मीद है, लेकिन परीक्षा की अधिसूचना अप्रैल 2026 की तय समयसीमा के बाद भी जारी नहीं की गई है। शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बीपीएससी टीआरई-4 समेत सभी लंबित भर्तियां जल्द पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा, ''अब कोई भी भर्ती लंबित नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि शिक्षा क्षेत्र बिहार के समग्र विकास की मजबूत नींव बने।''

नियम-कानूनों को सरल बनाने से संबंधित लंबित कार्य 15 दिनों में निपटाएं : के के पाठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव के के पाठक ने बिहार में नियम-कानूनों को सरल बनाने से जुड़े 'डीरेगुलेशन चरण-दो' के तहत लंबित सभी मामलों को अगले 15 दिनों के भीतर निपटाकर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पाठक ने शुक्रवार को यहां राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार सुगमता में सुधार लाने और पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से 'डीरेगुलेशन चरण-एक' और 'चरण-दो' की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। पाठक ने कहा कि व्यावसायिक कानूनों के तहत छोटी तकनीकी चूकों के लिए कारावास जैसे कठोर प्रावधानों को हटाकर उन्हें अर्थदंड में बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। विशेष सचिव ने कहा कि यदि कोई सुधार एक से अधिक विभागों से संबंधित है तो कैबिनेट सचिवालय विभाग समन्वय की भूमिका निभाए, ताकि फाइलें लंबित न रहें। उन्होंने सभी विभागीय नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शुक्रवार प्रगति रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय को भेजने का निर्देश दिया। पाठक ने राज्य के सभी विभागों को अपने कार्यक्षेत्र में अनावश्यक अनुपालन बोझ (कम्प्लायंस बर्डन) कम करने और चरण-दो के तहत चिन्हित सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता 2026 के नए मानकों को राज्य के भवन उपविधियों (बिल्डिंग बायलॉज) में शामिल करने पर भी चर्चा हुई।

मयूरभंज जिले में नए विद्युत उपकेंद्र से 15,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा : उपमुख्यमंत्री देव

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने शुक्रवार को मयूरभंज जिले के देउली में 33/11 केवी क्षमता वाले एक विद्युत उपकेंद्र का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। यह उपकेंद्र जिले की छह पंचायतों जैसे चुहाटा, कनिमाहुली, नुगांव, झालियामारा, अलाकुडा और देउली में 15,000 से अधिक परिवारों को बिजली प्रदान करेगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, मैं उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि वे लागत कम कर सकें और पूरे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे सकें। इस अवसर पर आवास और शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि विश्वसनीय बिजली ग्रामीण विकास के आधार के रूप में कार्य करती है तथा मयूरभंज में जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। इस सुविधा की स्थापना टाटा पावर और ओडिशा सरकार के संयुक्त उद्यम टीपी नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीएनओडीएल) द्वारा की गई है।

मणिपुर में भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ी

इंफाल/भाषा। मणिपुर में भाजपा नेता एलंगबम जॉनसन ने शुक्रवार को राज्य सरकार की जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करने में ''विफलता'' का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जॉनसन ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। जॉनसन ने 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था। उन्होंने कहा, ''तीन मई, 2023 से हम जनता की इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ने में असमर्थ रहे हैं। केइसमथोंग में अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद मैंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया है। मैं प्रदेश प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रहा हूं और पार्टी की सदस्यता त्याग रहा हूं।''जॉनसन ने कहा कि मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करने में सरकार की ''विफलता'' ही इस्तीफे का मुख्य कारण है।

बिहार: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों ने संभाला कार्यभार, गिनाईं सरकार की प्राथमिकताएं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद शुक्रवार को नवनियुक्त मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभाला और सरकार की प्राथमिकताओं को लोगों के सामने सामने रखा। मंत्रियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सहकारिता, समाज कल्याण और जन वितरण प्रणाली समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार एवं पारदर्शिता लाने की बात कही।

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता निशांत कुमार ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनने और सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता तक त्वरित सेवा पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जाएगा।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड में बदलने का आदेश जारी: ऊर्जा मंत्री शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर प्रणाली को बंद करने और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड में बदलने का फैसला किया है। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल मिलेगा। मई 2026 की खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों और केस्को कानपुर में लागू यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगी।

ऊर्जा मंत्री ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिये उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की स्वत: रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एएमआईएसपी एजेंसियों के माध्यम से 'मैनुअल रीडिंग' लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं हैं या गलत दर्ज हैं, उनके लिए विमरण कंपनियों के स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही उपभोक्ता संबंधित विद्युत वितरण निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट एवं 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से भी अपना बिल प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश में अब सभी नए विद्युत संयोजन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही जारी किए जाएंगे। पूर्व में प्री-पेड व्यवस्था लागू होने के दौरान समायोजित की गई सुरक्षा धनराशि को अब विद्युत प्रदाय संहिता-2005 एवं कॉस्ट डाटा बुक-2026 के प्रावधानों के अनुसार चार समान मासिक किस्तों में उपभोक्ताओं के बिलों में जोड़ा जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पोस्टपेड उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन का भुगतान समय और उसके बाद सात दिन की डिस्कनेक्शन अवधि प्रदान की जाएगी। निर्धारित समय तक भुगतान न होने पर विद्युत प्रदाय संहिता एवं शुल्क आदेश के अनुसार विलंब अधिभार लागू होगा।

दो दिनों में 35 पुलिस मुठभेड़: तीन अपराधी ढेर, 36 घायल, कई गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पिछले दो दिनों में मुठभेड़ की 35 कार्रवाइयां कीं तथा इस दौरान तीन कथित अपराधी मारे गए, 36 से अधिक घायल हुए और 60 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने कहा कि यह कार्रवाई राज्य सरकार की ''अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति'' और संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान ऐसे समय में चलाया गया जब एनसीआरबी की 'क्राइम इन इंडिया 2024' रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अपराध दर प्रति एक लाख आबादी पर 180.2 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 252.3 से कम है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार छह और सात मई को मुजफ्फरनगर, हरदोई, मथुरा, बरेली, गोंडा, इटावा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शामली, वाराणसी, फतेहपुर, कौशांबी, अमरोहा, रायबरेली, जौनपुर और मऊ समेत कई जिलों में मुठभेड़ हुईं।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, ज्यादातर मामलों में आरोपियों ने भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में अधिकतर संदिग्धों के पैरों में गोली लगी। इन मुठभेड़ों में 36 आरोपी घायल हुए, जबकि 20 अन्य को तलाशी अभियानों में बिना चोट के गिरफ्तार किया गया। दो अलग-अलग घटनाओं में चार पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर है। पुलिस के अनुसार सबसे ज्यादा सात मुठभेड़ मुजफ्फरनगर में हुईं, जहां 10 आरोपियों को गोली लगी और 11 अन्य गिरफ्तार किए गए। ये मुठभेड़ लूट, डकैती, मोबाइल छीनने और चोरी के मामलों से जुड़ी थीं।

बिहार में जातिवाद और वंशवाद की राजनीति कर रहा राजग : तेजस्वी यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बिहार के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) पर राज्य में जातिवाद और वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता में यह भी आरोप लगाया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनी राजग सरकार ''अस्थिरता'' और ''निष्क्रियता'' से घिरी हुई है।

यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, '' वह मुझे युवराज कहते थे। लेकिन हाल में बने मंत्रिमंडल में कम से कम 17 मंत्री वंशवाद की राजनीति की उपज हैं।'' उन्होंने कहा कि वर्तमान मंत्रिमंडल में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्रों को मंत्री बनाया गया है।

उनका इशारा निशांत कुमार, संतोष कुमार सुमन और नीतीश मिश्र की ओर था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्रों को बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया गया। उन्होंने दावा किया, ''निकट भविष्य में आप दोनों उपमुख्यमंत्रियों के पुत्रों को भी सक्रिय राजनीति में आते देखेंगे।'' यादव ने कहा कि अब राजग नेताओं को वंशवाद की राजनीति पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी दलों में व्याप्त वंशवाद भी देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी कम कर दिया गया है।

नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने चार महीने में आठ डॉल्फिन को बचाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत की पहली 'डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस' ने अब तक आठ गंगा डॉल्फिन को बचाकर वापस नदी में छोड़ दिया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चलाए गए अपने ताजा बचाव अभियान की जानकारी देते हुए यह बताया।

एनएमसीजी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर बताया कि गोंडा में एक वयस्क नर गंगा डॉल्फिन नहर में फंसी मिली थी। उसने बताया कि वह नदी की धारा से भटक गई थी और उथले पानी में फंसी होने के कारण हर पल कमजोर होती जा रही थी। उसने कहा, ''ऐसे में एक ही उम्मीद थी, एनएमजीसी की डॉल्फिन एम्बुलेंस। उत्तर प्रदेश वन विभाग और 'टर्टल सर्वाइवल अलायंस (टीएसए) इंडिया' की टीम मौके पर पहुंची तथा 13 घंटे की लगातार मेहनत के बाद डॉल्फिन को सुरक्षित बाहर निकाला गया, चिकित्सकीय जांच की गई और राप्ती नदी में फिर से छोड़ दिया गया। एक जीव फिर से अपने घर लौटा।''

एनएमसीजी ने इस अभियान को विशेष बचाव सुविधा की एक और सफलता बताते हुए कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत इस वर्ष के आरंभ में शुरू की गई डॉल्फिन एम्बुलेंस गंगा नदी की विलुप्तप्राय डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में उभरी है।

उसने कहा, ''यह डॉल्फिन एम्बुलेंस सिर्फ एक वाहन नहीं है। यह भारत की इस प्रकार की पहली सुविधा है जिसे जनवरी 2026 में शुरू किया गया था और तब से अब तक आठ गंगा डॉल्फिन को बचाकर वापस नदी में छोड़ा जा चुका है।''

मणिपुर में कानून-व्यवस्था के ध्वस्त होने के लिए केंद्र, राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंफाल/भाषा। भारत-म्यामां सीमा के पास नगा इलाके में सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा कई घरों पर हमला कर उन्हें जलाए जाने की घटना के एक दिन बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि मणिपुर में कानून-व्यवस्था के 'पूरी तरह से चरमरा जाने' के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारे जिम्मेदार हैं।

कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष ओ. इबोबी सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण वाली असम राइफल्स मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड में अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी पूछा कि बृहस्पतिवार की घटना पर बल 'मूक दर्शक' क्यों बने रहे। सिंह ने कहा, असम राइफल्स कल (बृहस्पतिवार) हुई घटना स्थल के पास तैनात हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति का प्रभारी कौन है? क्या राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार? वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते या बच नहीं सकते। उन्होंने ये टिप्पणी कथित तौर पर भारी हथियारों से लैस होकर म्यांमा से आए उग्रवादियों द्वारा कामजोंग जिले के नामली, वांगली और चोरो सीमावर्ती नगा गांवों में कई घरों पर हमला करने और उन्हें जलाये जाने के एक दिन की। ये गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित हैं। नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल. कीशिंग ने दावा किया था कि यह हमला सीमा पार से कुकी नेशनल आर्मी (बर्मा) और पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने किया था।

सिंह ने कहा, चाहे सत्ताधारी पार्टी के विधायक द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक आक्रमण, यह कानून-व्यवस्था की पूर्ण विफलता है। हाल ही में, ट्रोंगलाओबी में भी बम हमले में दो बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने कहा,हमने सुना कि घटनास्थल पर मणिपुर पुलिस के कुछ निहत्थे जवान तैनात थे जबकि उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार कामजोंग जिले के लोगों के प्रति गंभीर नहीं है, जबकि असम राइफल्स मूकदर्शक बनी हुई है।

सुविचार

बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय-जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेहतर भविष्य के लिए करें जनसंख्या नियंत्रण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में पूछे गए एक सवाल का यह जवाब देकर जनभावनाओं का विशेष ध्यान रखा है कि 'कोई भी कानून तभी सफल हो सकता है, जब उसे जनता का सहयोग मिले।' वैसे, आज लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। अगर अब सरकार इस दिशा में कोई कानूनी कदम उठाती है तो उसे समर्थन मिलने की ज्यादा संभावना है। हर राज्य में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत भी नहीं है। सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां कुल प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मणिपुर में यह प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से ऊपर है। अगर आजादी के तुरंत बाद जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस नीतियां लागू की जातीं तो आज देश में हालात बहुत बेहतर होते। भारत में जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन सुविधाएं उस अनुपात में नहीं बढ़ाई गईं। जो लोग वोटबैंक के लिए जनसंख्या बढ़ाने का आह्वान करते रहते हैं, उन्हें गर्मियों में एक दिन ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करना चाहिए। पता चल जाएगा कि आम आदमी ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है! आज हर जगह भीड़ ही भीड़ है। बस स्टैंड पर अपनी बारी आने में पसीने छूट जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बेरोजगारी का दंश भोगते युवा जाएं तो कहां जाएं? एक-एक पद के लिए हजारों लोग कतारों में खड़े हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, साफ हवा, पानी, भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिएं। क्या आम आदमी को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल रही हैं?

हमारे कई शहरों का एक्यूआई सामान्य से ज्यादा है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बाजारों में मिलावटी और नकली चीजों की भरमार है। कई लोग नकली दूध, पनीर, मावा, मिठाई और दवाई तक बेच रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई का डर नहीं है और इस बात की गारंटी है कि माल तुरंत बिक जाएगा। हमारे शहर इतनी जनसंख्या का दबाव बर्दाश्त करने के लिए नहीं बसाए गए थे। प्राय: नेतागण इस मुद्दे पर बोलने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि इससे लोग नाराज हो जाएंगे और उनके वोट टूट जाएंगे। हालांकि अब स्थिति बहुत बदल गई है। लोग इस मुद्दे पर खुलकर बात करने लगे हैं। अगर नेतागण इस पर चर्चा करेंगे तो लोग सुनेंगे। भारत में मौजूदा जनसंख्या के लिए भोजन, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, परिवहन जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या जो बच्चे भविष्य में जन्म लेने वाले हैं, वे बेहतर सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? क्या हम चाहते हैं कि वे भी रोजगार के लिए धक्के खाएं और लंबी कतारों में इंतजार करते हुए अपनी जवानी खपाएं? जिन राज्यों में जन्म दर 2.1 या इससे नीचे चली गई, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। जिन राज्यों में जन्म दर सामान्य से ज्यादा है, वहां लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह काम जोर-जबरदस्ती से नहीं हो सकता। चीन ने ऐसा ही किया था, जिसके नतीजे घातक रहे। वहां एकल संतान नीति के कारण कई परिवारों में रिश्ते खत्म हो गए। भारत में प्रोत्साहन से ही अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। जिन लोगों की तीन से कम संतानें हों, उन्हें लाभ दिए जाएं। उनके लिए सरकारी योजनाओं में विशेष प्रावधान किए जाएं। उनके बच्चों को प्रवेश परीक्षाओं में कुछ अंकों की रियायत दे सकते हैं। उन्हें बैंक जमा और बचत योजनाओं में ज्यादा ब्याज देना चाहिए। इससे ज्यादा जन्म दर वाले राज्य भी प्रतिस्थापन स्तर पर आने के लिए पूरे प्रयास करेंगे।

ट्वीटर टॉक

महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती के मौके पर आभार कार्यक्रम का आयोजन! हमारी सरकार वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और समान अवसर प्रदान करने के लिए लगातार पक्के इरादे के साथ काम कर रही है।

-भजनलाल शर्मा

विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनकल्याण, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, हम उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं।

-वसुंधरा राजे

मैंने द रॉकेट लर्निंग फाउंडेशन की टीम के साथ सेक्रेटेरिएट में मौजूद ऑफिस में एक काम की चर्चा की। यह संस्था आंगनवाड़ी नेटवर्क और ज़मीनी स्तर के वर्कर्स के साथ मिलकर प्रो बोनो बेस्ड पहलों के ज़रिए शुरुआती बचपन की शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में ज़रूरी काम कर रही है।

-दिया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

प्रकृति का संतुलन

अवंतिका नगर के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी फसल पकने से पहले ही पक्षी उसे खा जाते थे। समस्या से तंग आकर वे राजा के पास पहुंचे। राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि नगर के सभी पक्षियों को मार दिया जाए। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और कुछ ही समय में सारे पक्षी समाप्त कर दिए गए। शुरुआत में नगरवासी बहुत खुश हुए। उन्होंने बिना किसी डर के नई फसल बोई, क्योंकि अब पहरेदारी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब फसल काटने का समय आया, तो सभी चकित रह गएखेतों में अनाज लगभग नहीं था। स्थिति इतनी खराब हो गई कि अगले वर्ष बोने के लिए भी बीज नहीं बचे। राजा ने कारण की खोज करवाई। तब पता चला कि मिट्टी के कीड़े बीजों को खा गए थे। पहले पक्षी इन कीड़ों को खाकर फसल की रक्षा करते थे, लेकिन उनके न रहने से कीड़ों की संख्या बढ़ गई और पूरी फसल नष्ट हो गई। इस गलती का अहसास होने पर नगरवासियों ने फिर से पक्षियों को पालना शुरू किया और दूसरे स्थानों से भी पक्षी लाकर बसाए। धीरे-धीरे स्थिति सुधरी। इस घटना से सभी ने सीखा कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है।

सामयिक

मणिपुर हिंसा : आक्रोश में अवसर तलाशता विपक्ष

संजय सक्सेना

मोबाइल : 9454105568

मणिपुर को लेकर राजनीतिक कारणों पर रोशनी डाली जाये तो ऐसा लगता है कि मणिपुर की हिंसा पर हो-हल्ला करके विपक्ष अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहता है। वे कुकी समुदाय को अपना सहारा बताते हैं, जबकि मैतेई बीजेपी समर्थक हैं। इसलिये वह संसद में चर्चा की मांग करके सदन जाम करते हैं, जो बीजेपी को कमजोर दिखाता है। यहां के हालात को देखते हुए केंद्र ने अमित शाह को भेजा, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं।

भारत के पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य मणिपुर पिछले कई सालों से क्षेत्रीय हिंसा की खबरों के कारण पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ मोदी सरकार लगातार दावे कर रही है कि मणिपुर में हालात बेहतर करने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, वहीं विपक्ष मणिपुर के बिगड़े हालात के लिये मोदी सरकार को कसूरवार ठहराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। विपक्ष इतना शोर करते हुए अन्य कहीं नहीं देखा जाता है, जितना मणिपुर को लेकर मचाया जा रहा है। क्या है इसके पीछे राजनीतिक कारण? क्या यहाँ की हिंसा जातियों में आपसी क्लेश का मामला है? कहा जाता है कि मणिपुर का संघर्ष मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच है, यह बात कितनी सच है? मणिपुर की समस्या को कहीं राजनेताओं के आरोप-प्रत्यारोप ने और जटिल तो नहीं बना दिया है। यह तमाम सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बेहद जरूरी है। गौरतलब हो, मणिपुर की हिंसा की जड़ें गहरी हैं। राज्य की अधिकांश आबादी मैतेई समुदाय की है, जो इंफाल घाटी में रहते हैं और राज्य की राजनीति व अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरी ओर कुकी और नागा जैसे आदिवासी समुदाय पहाड़ी इलाकों में बसे हैं, जो संसाधनों और प्रतिनिधित्व में भेदभाव का आरोप लगाते हैं। तीन साल पहले मई में उच्च न्यायालय के मैतेई को जनजातीय दर्जा देने के सुझाव से कुकी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया, जो हिंसा में बदल गया। तब से मणिपुर में हिंसा की आग लगातार सुलग रही है, जिसमें सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और पचास हजार से अधिक लोग विस्थापित हैं।

हिंसा केवल जातीय कलह तक सीमित नहीं रही। हाल ही में अप्रैल 2026 में बिष्णुपुर और इंफाल में फिर झड़पें भड़कीं, जहां सुरक्षा बलों पर हमले हुए और कर्फ्यू लगाना पड़ा। कुकी उग्रवादियों पर छह लोगों की हत्या का आरोप लगा, जिससे तनाव बढ़ा। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमीन हथियाने और संसाधनों पर कब्जे का इल्जाम लगाया। मैतेई कहते हैं कि कुकी अवैध प्रवासियों को बसाने की साजिश रच रहे हैं, जबकि कुकी विकास में हिस्सेदारी की मांग करते हैं। यह आपसी कलह इतिहास से चली आ रही है, जब मैतेई राजाओं ने कुकी को पहाड़ों में बसाया था, लेकिन अब दोनों के बीच दुश्मनी गहरी हो गई है। उधर, विपक्ष इसी कलह को राजनीतिक हथियार बनाने से जुड़ा है। कांग्रेस और अन्य दल बीजेपी सरकार को हिंसा रोकने में नाकाम बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री की चुप्पी उदासीनता दिखाती है और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को हटाने की मांग करते हैं। राज्यसभा में खरगे ने श्वेत पत्र की मांग की, जबकि राहुल गांधी ने महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। विपक्ष का तर्क है कि बीजेपी मैतेई समुदाय को समर्थन देकर कुकी को नजरअंदाज कर रही है, जिससे हिंसा बढ़ी। इसके पीछे राजनीतिक कारण स्पष्ट हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, और विपक्ष इसे कमजोर करके उत्तर-पूर्व में अपनी जमीन मजबूत करना चाहता है। 2023 से संसद के सत्रों में विपक्ष ने मणिपुर को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया कि वे राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के बावजूद हालात नहीं सुधरे, तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत होने पर भी इच्छाशक्ति नहीं है। आने वाले चुनावों को देखते हुए विपक्ष बीजेपी को घेरना चाहता है, खासकर जब एनडीए के सहयोगी जैसे जेडीयू ने सरकार को समर्थन दिया।

खैर, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष के बीजेपी पर हमलावर रहने का कारण सत्ता की राजनीति है। विपक्ष जानता है कि मणिपुर का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की छवि खराब कर सकता है। वे मोदी सरकार की पूर्वोत्तर नीति पर सवाल उठाते हैं, जबकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के समय भी हिंसा होती थी। इसी के कारण मैतेई विधायकों पर जनता का गुस्सा फूटा क्योंकि उन्होंने केंद्र तक बात नहीं पहुंचाई। विपक्ष इसे भुनाकर अल्पसंख्यक कुकी वोटों को अपने पाले में लाना चाहता है। हाल में बीजेपी नेताओं के दौरे को कांग्रेस ने चुनावी ड्रामा बताया।हालांकि हिंसा मूल रूप से जातीय है। मैतेई को जनजातीय लाभ जैसे आरक्षण और जमीन अधिकार चाहिए, जो कुकी को खतरा लगता है। कुकी पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं और डरते हैं कि मैतेई घाटी से ऊपर आ जाएं। दोनों ने हिंसा की, घर जलाए, लेकिन सरकार की विफलता ने इसे लंबा खींचा। यहां 217 मौतें और हजारों लोगों का बेघर होना यह साबित करता है कि यह सामाजिक क्लेश है, न कि सिर्फ राजनीतिक। फिर भी विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बताकर शोर मचाता है।

मणिपुर को लेकर राजनीतिक कारणों पर रोशनी डाली जाये तो ऐसा लगता है कि मणिपुर की हिंसा पर हो-हल्ला करके विपक्ष अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहता है। वे कुकी समुदाय को अपना सहारा बताते हैं, जबकि मैतेई बीजेपी समर्थक हैं। इसलिये वह संसद में चर्चा की मांग करके सदन जाम करते हैं, जो बीजेपी को कमजोर दिखाता है। यहां के हालात को देखते हुए केंद्र ने अमित शाह को भेजा, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं। 2026 तक हिंसा जारी रहने से विपक्ष को लगातार मुद्दा मिलता रहता है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष परिपक्वता दिखाए, लेकिन वे लाभ उठाते हैं। बात प्रबुद्ध समाज की की जाये तो यह वर्ग कहता है कि मणिपुर हिंसा के समाधान के लिए दोनों पक्षों को बातचीत करनी होगी। मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन विश्वास बहाली जरूरी है। इसके साथ ही केंद्र को जनजातीय दर्जे पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। विपक्ष का शोर कम हो और सहयोग बढ़े, अन्यथा यह कलह राज्य को तबाह करता रहेगा। मणिपुर के लोग शांति चाहते हैं, राजनीति का खेल नहीं। यह संघर्ष जातीय कलह से उपजा है, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया। बीजेपी पर हमले से उनका एजेंडा चलता है, पर शांति सबकी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर, मणिपुर का दर्द गहरा है, जिसे हल करने के लिए एकजुटता जरूरी है।

नजरिया

बंगाल की हिंसा है लोकतंत्र पर धब्बा और बड़ी चुनौती

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

बंगाल की ताजा हिंसा केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी है। यदि हमने समय रहते राजनीति को स्वस्थ मूल्यों की ओर नहीं मोड़ा, तो नफरत और हिंसा लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी आत्मा को पहचाने। यह देश युद्ध और प्रतिशोध की नहीं, बल्कि शांति, सह-अस्तित्व और विश्वबंधुत्व की भूमि है। वसुधैव कुटुम्बकम् केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता का मूल दर्शन है।

पश्चिम बंगाल में हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनावों के बाद जिस प्रकार हिंसा, हत्याओं, आगजनी और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने केवल राज्य की शांति को ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत किया है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, किंतु जब यह उत्सव हिंसा, भय और प्रतिशोध में बदल जाए तो यह केवल राजनीतिक असफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत बन जाता है। बंगाल की ताजा हिंसक घटनाएं इसी चिंता को सामने लाती हैं। चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ था। लेकिन परिणामों की घोषणा के बाद जिस प्रकार राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक हुए, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब वैचारिक संघर्ष न रहकर प्रतिशोध और वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें, कई लोगों की हत्याएं और विशेष रूप से सुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना दिया। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह क्यों बची रहनी चाहिए?

यह विडंबना है कि भारत, जिसने विश्व को अहिंसा, करुणा और वसुधैव कुटुम्बकम् का मंत्र दिया, आज वही देश राजनीतिक हिंसा के कारण अपनी छवि धूमिल करता दिखाई देता है। महात्मा गांधी ने राजनीति को नैतिकता और सेवा से जोड़ा था, लेकिन आज राजनीति सत्ता, प्रतिशोध और भय का माध्यम बनती जा रही है। बंगाल की हिंसा इस बीमारी का एक भयावह उदाहरण है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास हिंसा से अछूता नहीं रहा है। वामपंथी शासन के लंबे दौर से लेकर तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल तक राजनीतिक संघर्ष कई बार रक्तरंजित रूप में सामने आया। बूथ कब्जाने, विरोधियों को डराने, स्थानीय दबंगों और अपराधी तत्वों का राजनीतिक संरक्षण-ये सब बंगाल की राजनीति की कटु वास्तविकताएं रही हैं। सत्ता बदलती रही, लेकिन राजनीतिक संस्कृति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ सका। यही कारण है कि चुनाव परिणामों के बाद भी हिंसा का वातावरण बनता है और आम नागरिक भय तथा असुरक्षा के बीच जीने को मजबूर होता है।

दरअसल जब राजनीति विचार और जनसेवा से हटकर केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन जाती है, तब हिंसा उसका स्वाभाविक परिणाम बनती है। हार को लोकतांत्रिक विनम्रता से स्वीकार करने के बजाय प्रतिशोध का माध्यम बना लेना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों और विजय जुलूसों पर प्रतिबंध के बावजूद हिंसक घटनाएं हुईं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की नैतिक विफलता भी है। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव परिणामों पर सवाल उठाना और राजनीतिक टकराव को तीखा बनाना हो या भाजपा द्वारा आक्रामक राजनीतिक प्रतिक्रिया-दोनों पक्षों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे जनता को शांति और संयम का संदेश दें। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक दल अक्सर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें उकसाने का काम करते हैं। परिणामस्वरूप हिंसा सामान्य राजनीतिक व्यवहार का हिस्सा बनती जा रही है।

सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि राजनीतिक हिंसा की कीमत हमेशा आम जनता को चुकानी पड़ती है। जिन लोगों के घर जलते हैं, जिन परिवारों के सदस्य मारे जाते हैं, जिन छोटे व्यापारियों की दुकानें टूटती हैं, उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वे केवल उस हिंसक मानसिकता के शिकार बनते हैं जो सत्ता को मानवता से ऊपर मानती है। यह प्रश्न गंभीरता से पूछा जाना चाहिए कि आखिर राजनीतिक दल हिंसा का सहारा क्यों लेते हैं? जबकि इतिहास गवाह है कि हिंसा कभी स्थायी समाधान नहीं देती। हिंसा केवल भय, अविश्वास और प्रतिशोध को जन्म देती है। जो दल हिंसा को हथियार बनाते हैं, वे अंततः जनता की नजरों में अपना नैतिक अधिकार खो देते हैं। राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं।

आज भारत एक नए वैश्विक दौर में प्रवेश कर रहा है। दुनिया भारत को एक उभरती आर्थिक शक्ति, तकनीकी महाशक्ति और लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देख रही है। वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे सभ्य और नैतिक राष्ट्र का निर्माण भी होना चाहिए जहां राजनीति का आधार अहिंसा, संवाद और संवेदनशीलता हो। यदि राजनीतिक दल नफरत, सांप्रदायिकता और हिंसा को अपना हथियार बनाए रखेंगे, तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना रही है। गौतम बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, महावीर ने अहिंसा को जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया, गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर साम्राज्य को चुनौती दी। यह वही भारत है जिसने दुनिया को यह सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सह-अस्तित्व है। लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थों और गैर-राजनीतिक आपराधिक तत्वों के कारण देश की छवि प्रभावित हो रही है। अपराधी मानसिकता के लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वे दल बदलते रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल शक्ति और स्वार्थ की पूर्ति होता है। बंगाल की ताजा घटनाओं में भी ऐसे तत्वों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

समाधान केवल प्रशासनिक कठोरता में नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन में निहित है। सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा करनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र प्रतिद्वंद्विता का नहीं, सह-अस्तित्व का नाम है। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। किसी भी दल से जुड़े उपद्रवियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखकर संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बढ़ानी होगी। तीसरा, राजनीति के अपराधीकरण पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है। ऐसे लोगों को राजनीतिक दलों में प्रवेश ही न मिले जिनकी पृष्ठभूमि हिंसक और आपराधिक रही हो। राजनीतिक दलों को अपने भीतर नैतिक अनुशासन विकसित करना होगा। चैथा, समाज में लोकतांत्रिक शिक्षा और संवेदनशीलता का वातावरण बनाना होगा। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं में संवाद, सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। जब तक समाज स्वयं हिंसा को अस्वीकार नहीं करेगा, तब तक राजनीतिक हिंसा का अंत कठिन होगा।

बंगाल की ताजा हिंसा केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी है। यदि हमने समय रहते राजनीति को स्वस्थ मूल्यों की ओर नहीं मोड़ा, तो नफरत और हिंसा लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी आत्मा को पहचाने। यह देश युद्ध और प्रतिशोध की नहीं, बल्कि शांति, सह-अस्तित्व और विश्वबंधुत्व की भूमि है। वसुधैव कुटुम्बकम् केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता का मूल दर्शन है। यदि राजनीति इस दर्शन से विमुख होगी, तो लोकतंत्र केवल सत्ता संघर्ष बनकर रह जाएगा। पश्चिम बंगाल को अब हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति से बाहर निकलकर विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही लोकतंत्र की गरिमा है, यही जनता की अपेक्षा है और यही विकसित भारत का मार्ग भी।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

'बार आपका इंतजार कर रहा है': वकील की याचिका खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने सुनाया किस्सा

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय में उस समय एक दुर्लभ क्षण देखने को मिला जब भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अपनी वकालत के शुरुआती दिनों का एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि न्यायिक अधिकारी बनने की आकांक्षा रखने के लिए कैसे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने पहले उनसे नाराजगी जताई और बाद में कहा कि बार आपका इंतजार कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश ने यह किस्सा न्यायिक सेवा की एक अभ्यर्थी का हौसला बढ़ाने के लिए सुनाया जिसने एक परीक्षा पत्र के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने प्रेरणा गुप्ता की याचिका खारिज कर दी लेकिन वह अदालत कक्ष से मुस्कुराते हुए बाहर निकलीं।

जब गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश कीं तो प्रधान न्यायाधीश ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैं अपनी एक निजी कहानी साझा करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आप खुशी-खुशी यहां से जाएंगी क्योंकि हम आपकी याचिका स्वीकार नहीं कर सकते।

प्रधान न्यायाधीश ने विधि के छात्र के रूप में अपने अंतिम वर्ष का किस्सा सुनाया जब वह भी न्यायिक अधिकारी बनना चाहते थे। उन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना था। उन्होंने कहा, जब मैं अंतिम वर्ष में था, तब मैंने न्यायिक सेवा के लिए आवेदन किया था। उस समय अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते थे। जब तक परिणाम आए, प्रक्रिया बदल चुकी थी। पहले लोक सेवा आयोग चयन प्रक्रिया आयोजित करता था। फिर उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विषय विशेषज्ञ के रूप में काम करना था और उनकी राय आयोग पर बाध्यकारी होती।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उसी दौरान वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चले गए थे और उन्होंने वहां वकालत शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि उनके साक्षात्कार बोर्ड में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश वही थे, जिनके समक्ष उन्होंने कुछ ही दिन पहले दो महत्वपूर्ण मामलों में दलील पेश की थीं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, साक्षात्कार बोर्ड के लिए नामित सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश मुझे पहले से जानते थे, क्योंकि मैंने उनके समक्ष दो मामलों में बहस की थी। इनमें से एक मामला सुनीता रानी बनाम बलदेव राज था, जिसमें उन्होंने वैवाहिक विवाद में मेरी अपील स्वीकार की थी और सिजोफ्रेनिया के आधार पर तलाक के जिला न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया था।

प्रदर्शन

बिहार के पटना में शुक्रवार को पटना कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में बीपीएससी टीआरई 4.0 के उम्मीदवारों ने टीआरई 4 अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिलने के कुछ दिन बाद श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व सीईओ मृत पाए गए

कोलंबो/भाषा। श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कपिला चंद्रसेना संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार को अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

चंद्रसेना को राष्ट्रीय विमानन कंपनी के लिए विमान खरीद में कथित दलाली लेने के मामले में मार्च में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्हें मंगलवार को जमानत मिली थी।सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) एफ यू वूटलर ने कहा कि चंद्रसेना का शव उनके घर से बरामद किया गया।'डेली मिरर' अखबार के अनुसार, पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उनकी मौत फांसी लगाने से हुई।यह घटनाक्रम कोलंबो के मुख्य मजिस्ट्रेट असांगा एस बोडारगामा द्वारा चंद्रसेना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। उन पर अदालत द्वारा निर्धारित जमानत शर्तों के उल्लंघन का आरोप था। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को कोलंबो मुख्य मजिस्ट्रेट अदालत को बताया था कि इस मामले के मुख्य आरोपी तथा श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व सीईओ कपिला चंद्रसेना ने पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को छह करोड़ श्रीलंकाई रुपए की रिश्वत देने की बात स्वीकार की थी।चंद्रसेना ने कहा था कि 2015 में राजपक्षे के राष्ट्रपति रहने के दौरान उन्हें दक्षिणी ग्रामीण क्षेत्र स्थित उनके आवास पर तीन बार में दो-दो करोड़ श्रीलंकाई रुपए दिए गए थे।

बाहर से इमेज बनाना आसान है, असली खेल तो साफ दिल का है : नोरा फतेही

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही अपने शानदार डांस मूव्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अभिनेत्री ने बुधवार को समाज में 'अच्छी लड़की' को लेकर बनी रूढ़िवादी सोच पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने साफ किया कि किसी भी लड़की का अच्छा होना, उसके पहनावे या उठने-बैठने के तरीके से नहीं, बल्कि उसके दिल और ईमानदारी से तय होना चाहिए। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पॉडकास्ट का क्लिप शेयर किया। इस वीडियो में वह समाज द्वारा थोपे गए 'अच्छी लड़की' के पुराने ढर्रों पर चर्चा करती नजर आ रही हैं। उन्होंने समाज की दोहरी मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, हमने 'अच्छी लड़की' के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह गलत समझ लिया है। लोग अक्सर बाहर से

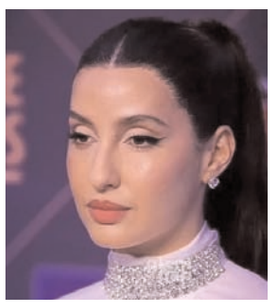

अच्छी इमेज बना लेते हैं, लेकिन उनकी असल कहानी पीछे कुछ और ही होती है। यह सब बस एक दिखावा है।नोरा ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि अगर कोई लड़की क्रॉप टॉप या अपनी पसंद के कपड़े पहनती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरी इंसान है। उन्होंने कहा, असली अच्छाई इस बात में है कि आप किसी को दुख न पहुंचाएं, किसी को धोखा न दें और हमेशा सच बोलें।अभिनेत्री का कहना है कि हम गलत चीजों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा, एक लड़की की असली पहचान उसकी नीयत और व्यवहार से होनी चाहिए, न की उसके कपड़ों से। कोई भी अपनी एक अलग पहचान बना सकता है और खुद को जैसे चाहे पेश कर सकता है, लेकिन अंत में केवल यह मायने रखता है कि उसका दिल कितना साफ है, तब तक बस यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। नोरा की बात करें, तो वे एक प्रसिद्ध कनाडाई डांसर, मॉडल और अभिनेत्री हैं। 'सत्यमेव जयते' (2018) के 'दिलबर' गाने ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया, जो उस समय यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गानों में से एक था। इसके बाद अभिनेत्री ने 'साकी साकी' और 'कमरिया' जैसे गानों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई।

जश्न

नागपुर में शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्र जश्न मनाते हुए।

कुब्रा सैत ने गोल्डन टेंपल में टेका माथा

मुंबई/एजेन्सी

अपने लगातार व्यस्त शूटिंग शेड्यूल, ट्रैवल और निजी ज़िंदगी के बीच अभिनेत्री कुब्रा सैत ने हाल ही में आध्यात्मिक सुकून के कुछ पल बिताए। जी हाँ, कुब्रा ने अमृतसर के प्रसिद्ध गोल्डन टेंपल पहुंचकर न सिर्फ माथा टेका, बल्कि वहां से अपनी एक शांत और खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। इस तस्वीर में सादगी भरे पारंपरिक लुक में, सिर ढके हुए कुब्रा बेहद शांत और भावुक नजर आ रही हैं। पवित्र स्थल पर खिंचवाई गई तस्वीर के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है, समर्पण करने आई थी लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत मिल गई। ऐसा हमेशा होता है! इसके साथ ही उन्होंने वाहेगुरु, गोल्डन टेम्पल और पवित्र जैसे हैशटैग भी इस्तेमाल किए हैं, जिससे उनके शब्दों में आस्था, शांति और आध्यात्मिक संतोष साफ झलक रहा था।

गौरतलब है कि अपने दमदार अभिनय और बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा अक्सर फैंस के साथ अपनी निजी जिंदगी की झलकियां साझा करती रहती हैं। लेकिन इस बार उनका एक बेहद शांत, भावुक और आध्यात्मिक रूप देखने को मिला है। साथ ही फैंस ने भी कुब्रा की पोस्ट पर खूब प्यार बरसाया है। किसी ने तस्वीर को 'डिवाइन' बताया है, तो किसी ने 'शांतिपूर्ण' और 'आत्मिक' कहा है। कई लोगों ने उनकी इस बात से खुद को जोड़ा कि सच्चे मन से समर्पण करने पर अक्सर उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है।

'साइकिल गैप' में दिखेगी म्यूजिकल लव स्टोरी

मुंबई/एजेन्सी

भारतीय सिनेमा में समय के साथ लव स्टोरीज को पेश करने का तरीका काफी बदल गया है। दर्शकों को ऐसी फिल्में ज्यादा पसंद आती है, जिसमें म्यूजिक कहानी का अहम हिस्सा होता है। इस कड़ी में निर्देशक एम आर भारती की नई फिल्म 'साइकिल गैप' काफी चर्चा में है। यह फिल्म एक म्यूजिकल ट्रायंगल लव स्टोरी है, जिसमें संगीत किरदारों की भावनाओं को जोड़ने वाला पुल बनेगा। निर्देशक एम आर भारती ने अपनी इस नई फिल्म को लेकर खुलकर बात की है।

उन्होंने कहा, 'साइकिल गैप' एक ऐसी रिलेशनशिप ड्रामा फिल्म है, जहां संगीत कहानी के केंद्र में रहेगा। कई बार इंसान अपनी भावनाओं को शब्दों में पूरी तरह नहीं बता पाता, लेकिन संगीत उन भावनाओं को बहुत आसानी से व्यक्त कर देता है। यही वजह है कि इस फिल्म में गानों और संगीत को बहुत खास तरीके से इस्तेमाल किया गया है। भारती ने कहा, हमने फिल्म को आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से मॉडर्न अंदाज में बनाया है, लेकिन साथ ही इसमें पुराने दौर की क्लासिक म्यूजिकल रोमांस फिल्मों की भावनात्मक खूबसूरती को भी बनाए रखने की कोशिश की है। एम आर भारती पहले भी अपनी फिल्मों में गहरी और भावनात्मक कहानियां दिखाने के लिए पहचाने जाते रहे हैं। उनकी फिल्म 'अझियाधा कोलांगल 2' को दर्शकों और समीक्षकों ने काफी सराहा था। वहीं उनकी हालिया फिल्म 'ड्रीम गर्ल' ने प्यार, सपनों और यादों जैसे विषयों को एक अलग और अनोखे तरीके से पेश कर लोगों का ध्यान खींचा था। अब 'साइकिल गैप' के जरिए वह अपनी इसी भावनात्मक कहानी कहने की शैली को आगे बढ़ाने जा रहे हैं।

फिल्म के निर्माता और मुख्य अभिनेता नवाज ने भी 'साइकिल गैप' को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा से ऐसी म्यूजिकल लव स्टोरी पसंद रही हैं, जो सालों तक लोगों के दिलों में बनी रहती हैं। इस फिल्म को भी उसी भावना के साथ तैयार किया गया है, ताकि दर्शकों के दिमाग में किरदार और संगीत लंबे समय तक बने रहें। निर्देशक भारती की कहानियों में गहरी भावनाएं होती हैं।नवाज ने कहा, प्रोडक्शन कंपनी ट्यूब लाइट प्रोडक्शंस का मकसद ऐसी फिल्म बनाना होता है, जो युवा दर्शकों को आकर्षित करे, देखने में ताजगी भरी लगे और संगीत के मामले में भी यादगार साबित हो।फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें नवाज के साथ अभिनेत्री शेरी अग्रवाल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। शेरी अग्रवाल इस फिल्म के जरिए एक्टिंग में डेब्यू करने वाली है। इसके अलावा अभिनेता प्रभु शास्ता भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। 'साइकिल गैप' में संगीत देने का काम संगीतकार सतीश पद्मनाभन ने किया है। वहीं गानों को नरेश अय्यर, श्रीनिषा जयसीलन और कौशिक श्रीधरन जैसे प्रतिभाशाली गायकों ने अपनी आवाज दी है।

प्रियंका चोपड़ा जोनास अगली हॉलीवुड फिल्म रीसेट में ऑरलैंडो ब्लूम के साथ नजर आएंगी

लॉस एंजिलिस/भाषा

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास अपनी अगली हॉलीवुड फिल्म रीसेट में पाइरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी फिल्मों के मशहूर अभिनेता ऑरलैंडो ब्लूम के साथ नजर आएंगी।इस फिल्म का निर्माण अगस्त में शुरू होगा और इसका निर्देशन मैट स्मूकलर करेंगे। स्मूकलर 2020 में आई फिल्म वाइल्डफ्लावर के लिए जाने जाते हैं।फिल्म रीसेट में प्रियंका एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जो सुनसान जंगल में जागती है। उसे याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंची। उसके जीवित रहने का एकमात्र उपाय एक आकर्षक अजनबी पर भरोसा करना है। यह अजनबी शायद वैसा नहीं है जैसा वह खुद को बताता है।

स्मूकलर ने कहा, मैं एक ऐसी जोड़ी की तलाश में था जहां आकर्षण और अविश्वास सहजता

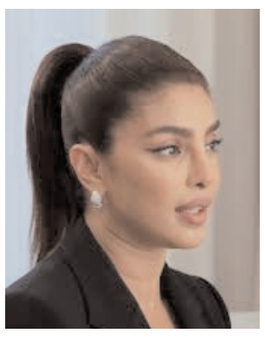

से एक साथ मौजूद रह सकें। प्रियंका और ऑरलैंडो में एक अद्भुत क्षमता है कि वे आपको एक ही समय में दोनों बातों पर विश्वास दिला देते हैं। इस फिल्म का निर्माण जॉन होएबर और एरिक होएबर अपनी कंपनी फ्रैट्रिसाइडल फिल्म्स के बैनर तले, माइकल लाजारोविच अपने कैमिकली ऑल्टर्ड और मैथ्यू रोड्स अपने रोड्स एंटरटेनमेंट के तहत करेंगे। प्रियंका इससे पहले फिल्म द ब्लफ में नजर आई थीं।

एक्शन और भावनाओं से भरपूर 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2'

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता रणदीप हुड्डा अपकमिंग वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' को लेकर बेहद उत्साहित हैं। रणदीप हुड्डा एक बार फिर से इंस्पेक्टर अविनाश का किरदार निभाते नजर आएंगे। अभिनेता ने हिंट देते हुए बताया कि एक्शन और भावनाओं से भरपूर 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' एक जबरदस्त सफर है और इस बार यह और भी मजेदार होने वाला है। रणदीप हुड्डा ने बताया, इस सीजन में अविनाश अपने असली और दमदार रूप में सामने आने के लिए तैयार है। वह अब सिर्फ जुर्म से नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने परिवार, अपनी सच्चाई और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इसका दायरा बड़ा है, एक्शन बिल्कुल असली है और भावनाएं कहीं ज्यादा गहरी हैं। यह एक कहीं ज्यादा जबरदस्त सफर है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला इस सीजन में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी। उन्होंने शो की तारीफ करते हुए कहा, 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेबाक और धमाकेदार है। एक्शन, भावनाएं और ट्विस्ट से भरी इस कहानी का हिस्सा बनना शानदार अनुभव रहा है। हर सीन अपनी अलग और खास अंदाज के साथ अलग स्तर पर ले जाता है। जियो हॉटस्टार के साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहा। दर्शक जिस रोमांच और ड्रामा का इंतजार कर रहे हैं, उसे हमने मिलकर तैयार किया है। निर्देशक नीरज पाठक ने सीजन 2 की खासियत बताते हुए कहा, हमने पहले सीजन की सभी पसंदीदा चीजों को इसमें शामिल किया है और उन्हें ज्यादा धमाल मचाने के माहौल में पेश किया है। अविनाश अब सिर्फ अपराधियों से नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम से भी लड़ रहा है जो उसके आसपास ढह रहा है। हमने एक्शन को बढ़ाया ही है, साथ ही भावनात्मक संघर्ष को भी और गहरा कर दिया है। इस बार लड़ाई जितनी बाहरी है, उतनी ही निजी भी है।

यह क्राइम थ्रिलर 1990 के दशक के उत्तर प्रदेश के अशांत माहौल पर आधारित है। कहानी में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा खुद को एक ऐसे तूफान में फंसा पाते हैं जो निजी और राजनीतिक दोनों स्तर पर उनका जीवन बदल देता है। बेटे के मर्डर केस में फंसने और शादी टूटने की कगार पर पहुंचने के बाद अविनाश को अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ती है।

सीजन 2 में रणदीप हुड्डा और उर्वशी रौतेला के साथ अमित सियाल, अभिमन्यु सिंह, रजनीश दुग्गल, शालिन भनोट और फ्रेडी दारूवाला जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। जियो स्टूडियोज के प्रस्तुत इस सीरीज को ज्योति देशपांडे, नीरज पाठक, गोल्ड माउंटेन पिक्चर्स और कृष्ण चौधरी ने प्रोड्यूस किया है। कहानी नीरज पाठक, संजय मासूम और समीर अरोड़ा ने लिखी है। 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' 15 मई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज को तैयार है।

'ऑपरेशन सिंदूर' की वर्षगांठ पर विवेक रंजन ने सेना को किया सलाम, बोले- शांति हमारा स्वभाव है, कमजोरी नहीं

मुंबई/एजेन्सी

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर फिल्म निर्माता-निर्देशक व लेखक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने देश की सेना को सलाम किया है। उन्होंने सशस्त्र बलों के साहस को नमन करते हुए कहा, एक साल बीत गया, जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि शांति हमारा स्वभाव है, लेकिन चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उस निर्णायक पल में पूरा देश एकजुट होकर खड़ा रहा। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा, आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली हमारी लीडरशिप, हमारी बहादुर सेना के साहस और हर उस भारतीय की भावना को नमन करता हूं, जो राष्ट्रीय संकल्प के उस पल में एकजुट होकर खड़े रहे। विवेक रंजन ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्ची कहानी को पूरी ताकत और सच्चाई के साथ दुनिया के सामने लाना चाहिए।

उन्होंने कहा, शायद सबसे

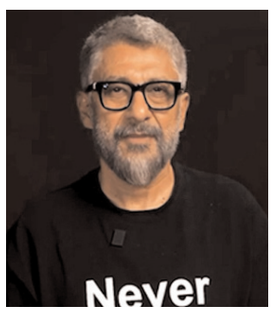

बड़ी श्रद्धांजलि जो हम दे सकते हैं, वह यह सुनिश्चित करना है कि ऑपरेशन सिंदूर की कहानी दुनिया को बताई जाए। पूरी सच्चाई और पूरी ताकत के साथ ताकि दुनिया को याद रहे कि किस चीज की रक्षा की गई, किस चीज का बलिदान दिया गया और मानवता को जिंदा रखने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी।

उन्होंने कहा, इतिहास युद्धों को याद रखता है। सभ्यताएं साहस को याद रखती हैं। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जो साहस और हिम्मत दिखाई, वो राष्ट्र की गरिमा और सुरक्षा की मजबूत मिसाल बनी। उन्होंने कहा कि शांति पसंद भारत हमेशा शांतिप्रिय रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वह दृढ़ता से अपने हितों और मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम है। विवेक रंजन ने हाल ही में बताया था कि उन्होंने भूषण कुमार के साथ नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी यह फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. 'टाइनी' ढिल्लों की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित है।

आचार्य कुलबोधिसूरीश्वर के सान्निध्य में सरस्वती मंत्र साधना करते हुए शिविरार्थी बच्चे और युवा वर्ग।

सरस्वती साधना से जागृत होगा सम्यक ज्ञान और आत्मबोध : आचार्य कुलबोधिसूरिश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। पुझल स्थित केसरवाड़ी जैन तीर्थ में विराजित आचार्यश्री कुलबोधिसूरिश्वरजी म. सा. की पावन निश्रा में आयोजित शिविरार्थी 'बच्चों एवं युवाओं के जीवन निर्माण शिविर' में शुक्रवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के वातावरण के बीच सरस्वती मंत्र साधना करवाई गई। इस अवसर पर आचार्यश्री ने सरस्वती साधना के वास्तविक स्वरूप एवं उसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मां भगवती सरस्वती की साधना केवल बुद्धि प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, विवेक, सहनशक्ति और आत्मजागृति की प्राप्ति के लिए की जाती है।

उन्होंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म में ज्ञान, विवेक और आत्मबोध को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी कारण जैन परंपरा में सरस्वती साधना का विशेष महत्व माना गया है। यहां सरस्वती केवल लौकिक विद्या की देवी नहीं, बल्कि सम्यक ज्ञान, शास्त्रबोध और आत्मिक जागरण की अधिष्ठात्री शक्ति मानी जाती हैं।

आचार्यश्री ने कहा कि जैन दर्शन में साधना का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि एवं कल्याण है। सरस्वती साधना व्यक्ति में शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, विवेकपूर्ण जीवन, मन-वचन-काया की पवित्रता तथा स्वाध्याय एवं आत्मचिंतन की भावना जागृत करती है। सरस्वती साधना के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जैन धर्म के तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में सम्यक ज्ञान का विशेष महत्व है और सरस्वती साधना उसी ज्ञान के द्वार खोलती है। इससे एकाग्रता, स्मरण शक्ति तथा वाणी में प्रभाव उत्पन्न होता है। वाणी की पवित्रता पर बल देते हुए आचार्यश्री ने कहा कि जैन धर्म में मितभाषिता और सत्य वचन का अत्यंत महत्व है। सरस्वती साधना वाणी को मधुर, संयमित और प्रभावशाली बनाकर अहंकार का नाश करती है।

उन्होंने बताया कि जैन परंपरा में ज्ञान पंचमी, शास्त्र पूजन, स्वाध्याय, आगम वाचन, नवकार मंत्र जाप एवं श्रुतदेवी स्तवन के माध्यम से सरस्वती आराधना की जाती है। सरस्वती साधना का मूल संदेश देते हुए उन्होंने कहा जिस ज्ञान से आत्मा का कल्याण हो, वही सच्ची सरस्वती है। कार्यक्रम के दौरान पंन्यासश्री ज्ञानबोधि विजयजी ने मध्याह्न सत्र में 'भोजन कैसे करें' विषय पर प्रेरणादायी प्रवचन प्रदान किया। शिविर के अंतर्गत शनिवार मध्याह्न मातृ-पितृ वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

कुशलचंद्र महाराज की पुण्य स्मृति को संकल्प दिवस के रुप में मनाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। संतश्री कुशलचन्द्रजी का स्मृति दिवस संघ समर्पण दिवस के रुप स्वाध्याय भवन मे मनाया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसंग पर गुणगान रुप में स्तुति की। वरिष्ठ स्वाध्यायी वीरेन्द्र कांकरिया ने पांचवे परिग्रह द्वार का विस्तृत विवेचन किया।

जैन रत्न श्रावक संघ, तमिलनाडु के पूर्व कार्याध्यक्ष नरेन्द्र कांकरिया ने महापुरुष के गुणगान करते हुए कहा कि कुशलचन्द्रजी का जन्म मारवाड़ के सेठो की रिया ग्राम में लादूराम चंगेरिया कानूबाई के यहां हुआ। बालवय में ही उनके पिताश्री का वियोग हो गया और बचपन में ही परिवार की जिम्मेदारी आ गई। संसार की नश्वरता को जानकर संतश्री को विरक्ति हो गई और आचार्यश्री भूधर का सान्निध्य पाकर दृढ़तम वैराग्य हो गया और जैन भागवती दीक्षा ले ली व प्रथम चातुर्मास मेड़ता में किया। उनके संयम की निर्मलता व तप तेज से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने आपके मुखारविन्द से जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। योग्यता होते हुए भी आपने आचार्य पद ग्रहण नही किया।

महापुरुषों के गुणगान करते हुए उनकी विशेषता बताते हुए कहा कि आचार्यश्री जयमल म.सा और कुशलचन्द्र म.सा का परस्पर इतना घनिष्ठ प्रेम रहा कि दोनों के शिष्य परिवार अलग-अलग होते हुए भी दोनों महापुरुष प्रायः साथ-साथ ही रहे । उनके मुखारविन्द से गुमानचंद्रजी, दुर्गादासजी आदि अनेक सन्त रत्नों की भागवती दीक्षाएं हुई। उनके गुरुदेव आचार्य भूधरजी का वियोग होने पर उन्होंने अपने गुरुभाई जयमल म.सा की तरह ही ज़िन्दगी भर आड़ा आसन नहीं करने की अर्थात नहीं सोने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। उनका संथारा पूर्वक समाधिमरण के पश्चात उन्होंने जिस बीज को अंकुरित पल्लवित-पुष्पित किया उसके संवर्धन का भार शिष्य गुमानचंद्रजी ने रत्नवंश के प्रथम आचार्य के रुप मे बखूबी निभाया ।

धर्म सभा मे महावीरचंद कर्णावट, गौतमचंद मुणोत, इन्दरचंद कर्णावट, हितेन कोठारी, महावीरचन्द बागमार, पदमचन्द, दीपक, योगेश श्रीश्रीमाल, लीलमचन्द बागमार, उच्छबराज गांग की सामायिक परिवेश में उपस्थिति थीं। हितेन कोठारी ने संकल्प मनोरथ चिन्तन सूत्र प्रस्तुत किया । सामूहिक नियम, प्रत्याख्यान,जैन संकल्प के पश्चात बाबू धनपतराज सुराणा ने मंगलपाठ किया।

बेटियों को शिक्षा के साथ-साथ घर के कार्यों का भी ज्ञान देना आवश्यक : साध्वीश्री पावनप्रभा

तेरापंथ महिला मंडल हनुमंतनगर ने आयोजित की कार्यशाला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के तेरापंथ महिला मंडल हनुमंतनगर के तत्वावधान में साध्वीश्री पावनप्रभाजी के सान्निध्य में मातृत्व दिवस पर 'मां-बेटी कार्यशाला' का आयोजन किया गया। अध्यक्ष संगीता तातेड़ ने साध्वीश्री पावनप्रभाजी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यशाला में शामिल माँ एवं बेटी की 10 जोड़ियों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा एक-दूसरे के प्रति काव्य के माध्यम से विचार व्यक्त किए।

साध्वीश्री पावनप्रभाजी ने अपने प्रवचन में कहा कि बेटियों को शिक्षा के साथ-साथ घर के कार्यों का भी ज्ञान देना आवश्यक है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को अच्छे संस्कार देना भी आवश्यक है, जिससे वे अपने भविष्य एवं वैवाहिक जीवन को सहजता और संस्कारपूर्वक निभा सकें। साध्वीश्री ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि यदि बचपन से ही बच्चों को कार्यों की आदत न डाली जाए, तो आगे चलकर उन्हें कठिनाई होती है। कार्यक्रम का संचालन सहमंत्री मीनाक्षी बोथरा ने किया तथा मंत्री पपीता दक ने धन्यवाद दिया।

साधर्मिक परिवारों के लिए 15 आइटम एवं स्कॉलरशिप वितरण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय वर्धमान साधर्मिक सेवा एवं जीव दया समिति द्वारा गुरुवार को एएमकेएम मेमोरियल ट्रस्ट के प्रांगण में संस्था की अध्यक्ष कमला मेहता, महामंत्री ललिता सुराणा, कोषाध्यक्ष विमला चोरड़िया, सहकोषाध्यक्ष आरती नाहर द्वारा प्रति माह की भांति इस माह भी 151/152वां अनाज खाद्य सामग्री एवं स्कॉलरशिप का वितरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्कॉलरशिप सौजन्यकर्ता सागरमल मंजू लोढ़ा, मुख्य अतिथि उपायुक्त पुलिस जीके कन्नन, ममता कर्णावत, दीपक आशा बैद की उपस्थित थे। इस अवसर जसवंतराज मंजू बरडिया व प्रकाशचंद चंदाबाई गादिया परिवार की ओर से परिवारजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संस्था को सहयोग राशि प्रदान की। रोजगार के लिए एक साधर्मिक को सिलाई मशीन राजकुमार राजकुमारी बैद की ओर से दी गई। इस अवसर संरक्षक सदस्य सज्जनराज मेहता, पृथ्वीराज बागरेचा, श्रेणिकराज नाहर, मूलचंद सुराणा, सुशीला नाहर, राजकुमारी बैद, शोभा कांकलिया आदि भी उपस्थित थे।

रुपचंद कुमट बने जैन प्रबुद्ध मंच के राष्ट्रीय संगठन सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। सकल जैन समाज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने की परिकल्पना के साथ जैन प्रबुद्ध मंच ट्रस्ट का गठन किया गया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुदीप जैन, अजमेर ने राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप बेंगलूरु के निवासी रूपचंद कुमट को नियुक्त किया है। इसके साथ ही संघ ने समाज की डिजिटल पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए 'जैनत्व एप्प' को लॉन्च किया है। कुमट ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए सभीजनों के सहयोग की अपील की। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कुमट को शुभकामनाएं दी।

उपकारी को अनदेखा करना, साक्षात परमात्मा का अपमान करने के समान : संतश्री कमलमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के आस्टिन टाउन स्थित जैन स्थानक में विराजित राष्ट्रसंतश्री कमलमुनिजी कमलेश ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए अपने प्रवचन में कहा कि व्यक्ति कितनी कठोर साधना कर ले, दान, त्याग, तपस्या चारों धाम की यात्रा कर ले, करोड़ों का दान कर दे, या संत भी बन जाए, पर जब तक नमक का वफादार नहीं बनता तब तक उसका धार्मिकता में प्रवेश नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पशु भी जिस घर का अन्न लेता है उसका वफादार बनकर उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक लूटा देता है। इंसान को उनसे सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इंसान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तो उसकी जाति और धर्म नहीं होता है वह मानवता पर कलंक है। ऐसे गद्दार व्यक्ति को विश्व के सभी महापुरुषों ने धर्म के अपात्र माना है।ङ्क मुनि कमलेशजी ने कहा कि 'नमक हलाल बनो, परंतु नमक हराम कभी नहीं बनना चाहिए,' इसको जीवन में उतारने वाला प्रत्येक व्यक्ति महापुरुष की श्रेणी में आ सकता है। राष्ट्रसंत ने कहा कि उपकारी को अनदेखा करना, साक्षात परमात्मा का अपमान करने के समान है। उपकारी के चरणों में यदि हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें तो भी उसके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जैन संत ने कहा कि पशु जगत कभी नमक हराम नहीं होता। सभी ग्रंथों मे उल्लेख आता है कि भगवान ने शेर, उल्लू, चूहा आदि को अपनी सवारी बनाया, परंतु इंसान को अपनी सवारी नहीं बनाया, क्यों इस पर गंभीरता से चिंतन करने की बात है ? जैन स्थानक पहुंचने पर संघ के वरिष्ठ जनों ने स्वागत किया।

सुशासन वही, जहां किसी के प्रति अन्याय नहीं, सबके प्रति न्याय हो : आचार्य विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बल्लारी। शुक्रवार को तोरंगल स्थित जिंदल साउथ वेस्ट में एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित जनों एवं विभिन्न विभागों में कार्यरत देश के अलग-अलग क्षेत्रों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि राजा और प्रजा के अपने-अपने कर्तव्य होते हैं। दोनों के लिए मर्यादाओं में रहना हितकारी होता है। पुण्य के प्रताप से कोई राजा बनता है। प्रजा उसकी शासन व्यवस्था में सुख-शांति से जीने की अभिलाषा रखती है। भेदभाव और अन्याय राजा की अयोग्यता एवं दुर्भाग्य के सूचक हैं, ऐसे राजा को प्रजापालक नहीं कहा जा सकता। गुणों से राजा यशस्वी बनता है, लेकिन गुणहीन या अवगुणी को इतिहास में कलंक के रूप में देखा जाता है।

लोकतंत्र का यह कमजोर और विषमतापूर्ण पक्ष है कि यहां आधी से कम आबादी का समर्थन पाकर भी कोई राजा बन जाता है, सत्ता पर काबिज हो जाता है। लोकतंत्र में गुण महत्वपूर्ण नहीं होते, वोट महत्वपूर्ण होते हैं। गिनती में गुणवान यदि पिछड़ जाता है तो उसकी गुणवत्ता एक ओर धरी रह जाती है और गिनती में यदि अवगुणी आगे रहता है तो वह राजा बन जाता है। इस खेल में न्याय-अन्याय का कोई नीति निर्धारण नहीं होता। यहां प्रजा का समर्थन प्राप्त कर अपराधी भी राजा बनने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और पर्याप्त समर्थन के अभाव में सज्जनता परास्त होकर दयनीय स्थिति में दिखाई देती है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि न्याय-नीतिपूर्ण सुशासन के लिए प्रजा जागरूक हों और उसके पास संख्या का पर्याप्त बल हो।

आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि जाति, भाषा, प्रांत और संप्रदायों का भेदभाव इतना जहरीला होता है कि वह मनुष्य को कभी न्याय, नीति, मानवता और कर्तव्य का बोध नहीं होने देता। इनके बलबूते पर अयोग्य भी सत्ता की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, लोकतंत्र न्याय की कसौटी नहीं है। नीति शास्त्र का मार्मिक कथन याद रखने जैसा है कि अयोग्य के पास आई हुई सत्ता की शक्ति सदैव लोगों के अन्याय व उत्पीड़न का ही काम करती हैं। भरण-पोषण का सामर्थ्य शोषण का माध्यम बन जाता है। उन्होंने कहा कि सुशासन उसे ही कहा जा सकता है जहां किसी के प्रति अन्याय नहीं होता और सबके प्रति न्याय की गारंटी होती है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन राज्य व्यवस्था इसी प्रकार की थी। पुराने जमाने में राजा अधिकारियों की शिकायत करने वाले को भी पर्याप्त संरक्षण देते थे। वर्तमान में न्याय की कानून व्यवस्था बहुत जटिल और अटपटी है।

कई घटनाओं में स्पष्ट लगता है कि यह अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा से मेल नहीं खाती। प्रातः तारानगर से पदयात्रा करते हुए आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी, गणि पद्मविमलसागरजी एवं सहवर्ती श्रमण तोरंगल स्थित विशाल औद्योगिक प्रतिष्ठान जिंदल साउथ वेस्ट पहुंचे जहां प्रतिष्ठान के अनेक पदाधिकारियों ने संतों का भावपूर्ण स्वागत किया और कई किलोमीटर तक उनके साथ पदयात्रा की।

केवीबी ने वित्तीय वर्ष में व्यवसाय में 14.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। करूर वैश्य बैंक (केवीबी) ने 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के परिणाम घोषित किए है । बैंक द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बचत जमा में 2505 करोड़ और रिटेल जमा में 8794 करोड़ की कुल वृद्धि दर्ज की है बैंक द्वारा बचत जमा और रिटेल जमा में यह वृद्धि पिछले दशक में सबसे अधिक है। इसी क्रम में बैंक का कुल व्यवसाय पिछले 5 वर्षों में 1.85 गुना से अधिक बढ़ा है । 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक ने अब तक का सर्वाधिक लाभ 2510 करोड़ दर्ज किया है जबकि बैंक का तिमाही लाभ 725 करोड़ रहा। कुल व्यवसाय में 14.93 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और 1.31 प्रतिशत तिमाही वृद्धि दर्ज की गई है जबकि जमा राशियों में 13.31 प्रतिशत वार्षिक और 0.93 प्रतिशत तिमाही वृद्धि रही इसी प्रकार ऋण पुस्तिका 16.88 प्रतिशत वार्षिक और 1.75 प्रतिशत तिमाही बढ़ी, जबकि खुदरा, कृषि और सूक्ष्म उद्योग (आरएएम) लोन में 17.69 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि रही। कासा अनुपात 26.91 प्रतिशत रहा। एनआइएम 4.11 प्रतिशत वार्षिक और 4.32 प्रतिशत तिमाही रहा। बैंक के अन्य आय में 13.93 प्रतिशत कि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है ।

वित्तीय परिणामों की घोषणा करते हुए करूर वैश्य बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश बाबू ने कहा कि बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 2,510 करोड़ रुपये का अब तक का उच्चतम लाभ और चौथी तिमाही के लिए 725 करोड़ रुपये का उच्चतम त्रैमासिक लाभ अर्जित किया है, जो विकास, लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता जैसे हमारे तीन प्रमुख मापदंडों द्वारा निर्देशित इसके मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। इस वर्ष अग्रिम जमा में 16.88 प्रतिशत और देनदारियों में 13.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि बैंक ने खुदरा, कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यम (आरएएम) क्षेत्रों में 17.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए अपनी मजबूत विकास गति को बरकरार रखने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि बैंक का कुल कारोबार 2,14,420 करोड़ से अधिक है, जिसमें 1,15,666 करोड़ रुपए की जमा राशि और 98,754 करोड़ रुपए का अग्रिम राशि शामिल है।

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

सुपर स्मार्ट चैंपियन बनने के लिए देव, गुरु और धर्म पर रखें अटूट निष्ठा व आस्था : संतश्री समकितमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के मागड़ी रोड स्थित गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन आराधना केन्द्र में बेंगलूरु चातुर्मास समिति-2026 के तत्वावधान में आयोजित अष्ट दिवसीय आवासीय 'समकित संस्कार शिविर' के छठें दिन संतश्री समकितमुनिजी की निश्रा में उत्तम शिक्षा और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के भीतर जीवन जीने की कला और उत्कृष्ट संस्कारों का ज्ञान दिया गया। बच्चों को संबोधित करते हुए डॉ. समकितमुनिजी ने कहा कि, हमारे सच्चे 'देव' केवल वीतराग अरिहंत और तीर्थंकर परमात्मा हैं। हमारे 'गुरु' वे हैं जो पांच महाव्रतों का कठोरता से पालन करते हैं और हमारा 'धर्म' वह है जो हमें अहिंसा, दया और करुणा का महान पाठ पढ़ाता है। जीवन में देव, गुरु और धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा और अटूट श्रद्धा लेकर जो आगे बढ़ता है, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। यह त्रिवेणी जीवन के हर मोड़ पर हमारी रक्षा और सुरक्षा करती है, क्योंकि ये हमें श्रेष्ठ संस्कार देते हैं और अंततः संस्कारों से ही हमारे जीवन की सुरक्षा होती है। जो इस सन्मार्ग का अनुसरण करता है, उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं टिक सकती। इसके साथ ही, गुरुदेव ने बच्चों को 'सुपर स्मार्ट चैंपियन' बनने का मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में चैंपियन बनने के लिए आपकी 'चॉइस' भी सुपर स्मार्ट होनी चाहिए। संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं एक पाप की ओर ले जाती है और दूसरी धर्म की ओर। छुट्टियों के इन दिनों में पाप और प्रमाद के बजाय 'धर्म' को चुनकर इन बालकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे सभी भगवान महावीर के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ङ्कशिविर में बच्चों ने केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन की नैतिक बातें जैसे 'मोबाइल फोन और टीवी' से पूर्णतः दूर रहकर भी आनंदित और खुश रहना, प्रातः जल्दी उठना, स्वयं का कार्य स्वयं करने, थाली में कभी जूठन नहीं छोड़ना।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.